राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण शनिवार 12 जुलाई 2025 वर्ष-8,अंक-143 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

रोजगार मेले में शनिवार को 51 हजार से अधिक नियुक्ति पत्र देंगे मोदी

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को यहां 16 वें रोज़गार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आज यहां बताया कि श्री मोदी इस अवसर पर नवनियुक्त कर्मचारियों को संबोधित भी करेंगे। रोज़गार मेला रोज़गार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। रोज़गार मेला युवाओं को उनके सशक्तीकरण और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देश भर में रोज़गार मेलों के माध्यम से अब तक 10 लाख से अधिक भर्ती पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह रोज़गार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। ये भर्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हो रही हैं। देश भर से चुने गए नए कर्मचारी रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय और अन्य विभागों तथा मंत्रालयों में शामिल होंगे।

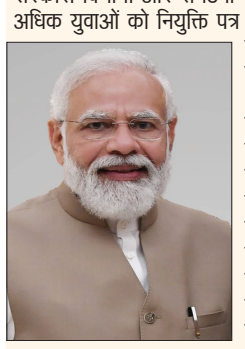

काम में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों को छोड़ने वाला नहीं : गडकरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। गुजरात के वडोदरा जिले में महिसागर नदी पर बने पुल के ढहने की घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बढ़ते पुल हादसों के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वे काम में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों के पीछे लग गए हैं। इतना ही नहीं उन्होंने कहा है कि दुर्भावनापूर्ण गलतियों पर ठोक देना चाहिए। मंत्री गडकरी ने कहा, एक्सीडेंट अलग चीज है और जो काम करते समय बेईमानी और फॉड करते हैं, वहां दूसरी चीज है। अगर गलती जानबूझकर नहीं की गई हो तब माफ कर देना चाहिए, लेकिन अगर गलती दुर्भावनापूर्ण की गई हैं, तब ठोक देना चाहिए। एक कार्यक्रम में उन्होंने यह टिप्पणी की। काम के रवैये को लेकर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि वह गड़बड़ होने पर जिम्मेदारों को डांट लगाते हैं। उन्होंने कहा, अगर कोई गड़बड़ हुई रोड पर तब छोड़ता नहीं हूं। अभी मेरा टारगेट है, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए, अब मैं ठेकेदार और अधिकारियों के पीछे लगूंगा। ये मेरे देश की संपत्ति है, मैं इसके साथ समझौता नहीं करूंगा। एक एक रोड में मेरे घर की दीवार है। जितनी चिंता मुझे मेरे घर की है, उतनी जिम्मेदारी मेरी उस रोड के साथ है। इसके साथ समझौता नहीं करूंगा। गुजरात पुल हादसा महिसागर नदी पर बने पुल के ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल पर खोज एवं बचाव अभियान रात के लिए रोक दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह अभियान शुक्रवार सुबह फिर से शुरू होगा क्योंकि दो व्यक्ति अब भी लापता हैं।

अमरनाथ यात्रा: अब तक 1.45 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन

जम्मू (एजेंसी)। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए बीते 8 दिन से अमरनाथ यात्रा जारी है। यहां अब तक 1.45 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। जबकि आज यानी शुक्रवार को 6,482 यात्रियों का एक और जत्था कश्मीर के लिए रवाना हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि 3 जुलाई को यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 1.45 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कहा, शुक्रवार को 6,482 यात्रियों का एक और जत्था भगवती नगर यात्री निवास से दो सुरक्षा काफिलों में घाटी के लिए रवाना हुआ है। पहले काफिले में 107 वाहन शामिल हैं, जिनमें 2,353 यात्री मौजूद हैं। ये जत्था सुबह 3:20 बजे बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुआ, जबकि दूसरे काफिले में 161 वाहन मौजूद हैं और उनमें 4,129 यात्री थे। ये काफिला सुबह 4:04 बजे नुनवान (पहलगाम) बेस कैंप के लिए रवाना हुआ है।

बता दें कि गुफा मंदिर में एक बर्फ का शिवलिंग है, जो चंद्रमा के चरणों के साथ बढ़ता और घटता है। भक्त मानते हैं कि यह बर्फ का शिवलिंग भगवान शिव की पौराणिक शक्तियों का प्रतीक है। श्री अमरनाथ जी यात्रा हिंदू भक्तों के लिए सबसे पवित्र तीर्थयात्राओं में से एक है। मान्यता है कि भगवान शिव ने इस गुफा में माता पार्वती को शाश्वत जीवन और अमरता के रहस्य बताए थे। गुरुवार को पहलगाम में छड़ी मुबारक (भगवान शिव की पवित्र गदा) का भूमि पूजन किया गया। छड़ी मुबारक के एकमात्र संरक्षक महंत स्वामी दीपेंद्र गिरि के नेतृत्व में श्रीनगर के दशनामी आखाड़ा भवन से पहलगाम ले जाया गया।पहलगाम में छड़ी मुबारक को गौरी शंकर मंदिर ले जाया गया, जहां भूमि पूजन हुआ। बाद में इसे मार्तंड सूर्य मंदिर ले जाया गया, जहां पूजा की गई और छड़ी मुबारक को मार्तंड सूर्य मंदिर के पवित्र झरने में स्नान कराया गया। छड़ी मुबारक 9 अगस्त को पवित्र गुफा मंदिर पहुंचेगी, जब यात्रा आधिकारिक रूप से समाप्त होगी।

ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार बोले एनएसए डोभाल, कहा...

ऑपरेशन सिंदूर हमारी सफलता, भारत को नुकसान के दावे खोखले, सबूत हैं तो दिखाओ: अजित डोभाल

चेन्नई (एजेंसी)। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल ने शुक्रवार को 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर पहली बार बयान दिया। उन्होंने अभियान की सफलता को लेकर खड़े किए जा रहे सवालों को सिरे से खारिज किया। विदेशी मीडिया को चुनौती दी कि अगर उनके पास भारत के नुकसान को लेकर कोई सबूत है तो उसे पेश करें।

आईआईटी मद्रास के 62वें दीक्षांत समारोह में कही। अजित डोभाल ने कहा कि हमने पाकिस्तान में नौ आतंकी ठिकानों को चुनकर निशाना बनाया। ये सीमावर्ती इलाके नहीं थे, बल्कि वो जगहें थीं जहां हमें यकीन था कि आतंकी मौजूद हैं। हम एक भी लक्ष्य से चूके नहीं और कोई अन्य जगह को निशाने पर लिया नहीं। हमला पूरी तरह सटीक और पूर्व-निर्धारित जानकारी के आधार पर किया गया था। महज 23 मिनट में पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस दौरान भारतीय वायुसेना और सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर ऐसी सामरिक एकता दिखाई, जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई।

उन्होंने कहा कि विदेशी मीडिया कोई भी फोटो या सैटेलाइट इमेज नहीं दिखा पाया और न ही यह बता पाया कि नुकसान क्या हुआ। एनएसए ने कहा, 'विदेशी प्रेस कहता रहा कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन मुझे एक फोटो दिखाइए जिसमें भारत का नुकसान नजर आया हो, यहां तक कि एक शीशा भी टूटा हो। हमसे कोई चूक नहीं हुई। हम उस पॉइंट तक सटीक थे जहां हमें पता था कि कौन कहां है।'

उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि आप मुझे एक भी तस्वीर या सैटेलाइट इमेजरी दिखा दीजिए जिसमें भारत को कोई नुकसान हुआ हो, यहां तक कि किसी कांच की खिड़की तक को नुकसान पहुंचा हो। इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय सेना की आधुनिक तकनीक और रणनीति ने अहम भूमिका निभाई।

उन्होंने कहा कि हम इस बात पर गर्व करते हैं कि इस ऑपरेशन में स्वदेशी और अत्याधुनिक सिस्टम जैसे ब्रह्मोस, एकीकृत एयर कंट्रोल और कमांड सिस्टम और बैटलफील्ड सर्विलांस की भूमिका निर्णायक रही। हमने उनकी पोजीशन का सटीक अनुमान लगाया और उस आधार पर हमला किया। डोभाल ने तंज कसते हुए कहा कि विदेशी मीडिया ने बड़े-बड़े दावे किए, लेकिन क्या उनके पास कोई सबूत है? 'न्यूयॉर्क टाइम्स' ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन क्या उन्होंने एक भी वैध इमेज दिखाई जो भारत पर हुए नुकसान की पुष्टि करे?

पाकिस्तान में हमला: बस से यात्रियों को उतारा और पहचान देखकर 9 लोगों को मार डाला

इस्लामाबाद (एजेंसी)। आतंकियों को पनाह देने के आरोपों से घिरा पाकिस्तान खुद भी इसका शिकार है। बीते रोज एक यात्री बस को रोका गया और सवारियों को उतारकर उनसे नाम पता पूछा और गोली मार दी। ऐसे करीब 9 लोगों की हत्या कर दी गई। बलूचिस्तान के अधिकारी इसे आतंकवादी घटना बता रहे हैं। इस साल मार्च में ही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक कर लिया था।

फिलहाल, स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, बलूचिस्तान के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि कम से कम 9 लोगों की हत्या कर दी गई है। उन्होंने बताया कि क्वेटा से लाहौर जाने वाली बस में सवार यात्रियों को उतारकर अगवा किया और गोली मार दी। घटना उत्तरी बलूचिस्तान के पास झोब शहर की है। रिपोर्ट के मुताबिक, हमलावरों ने बस को रोका, यात्रियों को उतारा और चुनकर पहचान कर 9 लोगों की हत्या कर दी।

पुलिस उपायुक्त नावेद आलम ने कहा कि यात्रियों को वाहनों से अगवा करने के बाद उन्हें गोली मारी गई थी। उन्होंने कहा कि शवों को बलूचिस्तान के बारखान जिले के रेखनी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने घटना की निंदा की और उसे आतंकवादी कृत्य करार दिया है। उन्होंने कहा, आतंकवादियों ने यात्रियों को बस से उतारा, पहचान की और बेरहमी से 9 मासूम पाकिस्तानियों की हत्या कर दी। रिपोर्ट के अनुसार, एक अधिकारी ने कहा कि हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। फिलहाल, उनकी तलाश जारी है।

मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुगती ने इसे खुला आतंकवाद बताया और तार फित्ना ए हिन्दुस्तान से जोड़े। बुगती का कहना है कि हमलावरों ने जानबूझकर पाकिस्तानी पहचान के कारण मासूम नागरिकों को निशाना बनाया है।

भोलेबाब जयकारो के साथ शुरु हुई कांवड़ यात्रा

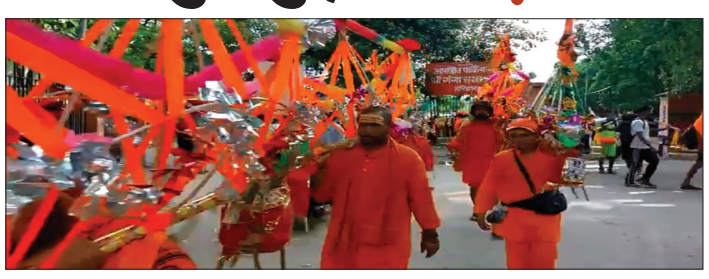

-यूपी से दिल्ली और फिर हरिद्वार तक कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक प्लान तैयार

-दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर भारी और हल्के वाहनों की आवाजाही पर रोक

नई दिल्ली (एजेंसी)। शुक्रवार से देशभर में सावन माह के शुरु होने के साथ भोलेबाब के जयकारों के साथ कावाड़ यात्रा भी शुरु हो गई। कांवड़िए गंगाजल लेने के लिए हरिद्वार की ओर निकल रहे है। आने वाले दिनों में इन कावड़ियों की संख्या और बढ़ेगी। जिसका सीधा असर कांवड़ मार्ग पर यातायात पर पड़ेगा। यह देखकर प्रशासन की ओर से भी तैयारियां की गई है। इसी क्रम में गुरुवार से दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। जबकि कई जगहों पर ट्रैफिक रूट डायवर्ट किया है।

इस साल कांवड़ यात्रा 11 से 23 जुलाई तक चलेगी, इसके बाद ट्रैफिक को लेकर पुलिस प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। गाजियाबाद पुलिस ने अगले 13 दिनों तक दिल्ली से मेरठ हाईवे पर भाई वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इसके बाद हल्के वाहनों पर भी रोक लगाने की तैयारी है। 18 जुलाई से इस मार्ग पर हल्के वाहनों की आवाजाही पर भी रोक रहेगी। इस दौरान भारी और हल्के वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग से भेजा जाएगा।

ओडिशा में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा...

अडाणी चला रहे ओडिशा सरकार

-इलेक्शन कमीशन भाजपा का कर रहा काम

भुवनेश्वर (एजेंसी)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को ओडिशा में कहा कि अडाणी ओडिशा सरकार चलाते हैं। अडाणी नरेंद्र मोदी को चलाते हैं। जब ओडिशा में जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है, तो लाखों लोग इसे देखते हैं। फिर एक नाटक होता है कि अडाणी और उनके परिवार के लिए रथ रोक दिए जाते हैं। इससे आपको ओडिशा सरकार के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। यह ओडिशा सरकार नहीं है, यह अडाणी जैसे 5-6 अरबपतियों की सरकार है। इसका लक्ष्य आपकी जमीन, जंगल और भविष्य को चुराना है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ओडिशा में भाजपा सरकार बनने के बाद पहली बार दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने भुवनेश्वर में आयोजित होने वाली संविधान बचाओ समावेश सभा को संबोधित किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल भी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में वोट चुराने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने नई साजिश शुरू की है। वह भाजपा के हिस्से का काम कर रहा है। अपना काम नहीं कर रहा है। राहुल ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 करोड़ नए वोटर आ गए। आज तक पता नहीं चल पाया कि ये वोटर्स कहां से आए। हमने इलेक्शन कमीशन से कई बार कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट, वीडियोग्राफी दीजिए। उन्होंने नहीं दिया। हम इलेक्शन कमीशन और भाजपा को बिहार का चुनाव चोरी नहीं करने देंगे।

भाजपा सरकार गरीबों को पैरा चुरा रही

राहुल ने कहा कि सरकार ओडिशा की गरीब जनता का पैसा चुराने का काम करती है। एक तरफ ओडिशा की गरीब जनता दलित, आदिवासी, कमजोर, किसान और मजदूर है और दूसरी ओर 5-6 अरबपति और भाजपा सरकार। इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ही ओडिशा की जनता के साथ मिलकर जीत सकता है। भाजपा पूरे देश में संविधान पर आक्रमण कर रही है।

कंपनियों को दिया जा रहा पैसा

राहुल गांधी ने कहा कि ओडिशा में ये(भाजपा) 5-6 बड़ी कंपनियों को आपका सारा धन दे रहे हैं। जल, जंगल और जमीन आदिवासियों की है और आदिवासियों की ही रहेगी। आदिवासियों को बिना पूछे जमीन से हटा दिया जाता है। ये सभी चीजें उनकी है।

नीतीश ने 1.11 करोड़ लाभार्थियों के खाते में पहुंचाए 1,100 रुपये

चुनाव से पहले एनडीए का मास्ट्रर स्ट्रोक

पटना (एजेंसी)। बिहार में विधानसभा चुनाव करीब आते ही, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सरकारी आवास से 1.11 करोड़ लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी की और विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रत्येक को 1,100 रुपये प्रदान किए। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से कुल 1,227.27 करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचे। इस कार्यक्रम में बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी उपस्थित थे।

सीएम नीतिश ने कहा कि पहले हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में 400 रुपये प्रदान करते थे, अब बढ़ाकर 1,100 रुपये किया गया है, ताकि विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत विधवाओं, विकलांगों और वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिल सके। नीतीश ने कहा कि समाज के हर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए हमलोग निरंतर काम कर रहे हैं, ताकि सभी एक सम्मानजनक तथा बेहतर जीवन व्यतीत कर सकें।

विपक्ष और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधकर सीएम नीतिश ने कहा कि बीते 20 सालों में जो कुछ भी हुआ है, उसमें उनका कोई खास योगदान नहीं है। 2005 से पहले कोई न कोई कुछ करता था, हम (राजद के साथ) गलती से दो बार वहाँ गए थे, लेकिन क्या इन लोगों ने कुछ खास किया है? उन्होंने कहा कि बिहार में राजनीति का एक नया युग शुरू होगा और इस बात पर जोर दिया कि सभी मिलकर विकास के पथ पर आगे बढ़ने वाले है। उन्होंने उपमुख्यमंत्री चौधरी की ओर देखकर कहा, हम भविष्य में कभी इधर-उधर नहीं जाएँगे, बल्कि राज्य के विकास के लिए साथ-साथ चलने वाले है।

आधार मेरी पहचान को क्यों झुठला रही मोदी सरकार... कांग्रेस सांसद ने उठाए सवाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर को जारी रखने की अनुमति देने पर बिहार में सयासी घमासान मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को जारी रखने की अनुमति देकर ''संवैधानिक दायित्व'' बताया। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने हालांकि, कवायद के समय पर सवाल उठाकर कहा कि बिहार में एसआईआर के दौरान आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड पर दस्तावेज के तौर पर विचार हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर तीखे सवाल उठाकर चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वे चल रहे अभियान के तहत मतदाता गणना के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को वैध दस्तावेजों के रूप में शामिल करने पर विचार करे। शीर्ष अदालत ने एसआईआर के समय और तरीके को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर विचार करने के लिए सहमत हुई है, इसकी अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 21 जुलाई तक का समय मिला है। अभी तक कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया है।

वहीं कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि एक ओर पूरी सरकार आधार को आधार मेरी पहचान कहकर प्रचारित करती है, अब कह रही है कि इसकी मान्यता खत्म हुई है। इसलिए चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से विचार कर सही तरीके से काम करना चाहिए। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट आख़िरकार इस पर फ़ैसला सुनाएगा। अब एनडीए को इसमें सहयोग करना चाहिए। बीजेपी भले ही वोटरों को काटने में लगी हो, लेकिन बाकी पार्टियों को समझना चाहिए कि आज क्या खेल हो रहा है।

विश्व जनसंख्या दिवस: नड्डा बोले-चुनौतियां हैं पर प्रशस्त हो रहा स्वस्थ भारत का मार्ग

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम रेखा गुप्ता समेत कई नेताओं ने 'विश्व जनसंख्या दिवस' पर देशवासियों को जागरूक किया। उन्होंने जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों का भी जिक्र किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, विश्व जनसंख्या दिवस' परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों से निपटने की हमारी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का मंच है। उन्होंने आगे कहा, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से केंद्र सरकार पूरे देश में आवश्यक परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान कर रही है, जिससे परिवार सशक्त हो रहे हैं और एक स्वस्थ भारत का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

इस साल की थीम, 'मां और बच्चे के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए गर्भावस्था का सही समय और अंतर,' माता और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए नियोजित माता-पिता बनने के महत्व पर जोर देती है। विश्व जनसंख्या दिवस 2025 का नारा- 'मां बनने की उम्र वही, जब तन और मन की तैयारी सही'- माता-पिता बनने के लिए शारीरिक और भावनात्मक रूप से तैयार रहकर सूचित और सशक्त निर्णय लेने के महत्व को रेखांकित करता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, विश्व जनसंख्या दिवस पर, हम एक न्यायपूर्ण, सशक्त और समतामूलक समाज के अपने दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं, जहां प्रत्येक व्यक्ति को अवसर, अधिकार और सम्मान प्राप्त हो। हमारे युवाओं को एक ऐसे भविष्य का हक है, जहां वे सूचित विकल्प चुन सकें, समानता के साथ जी सकें और बिना किसी सीमा के सपने देख सकें। आइए, हम समावेशी नीतियों, सतत विकास और हर जीवन को बेहतर बनाने की साझा प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ें, जिसके लिए हम जिम्मेदार हैं।

वहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक्स पर लिखा, विश्व जनसंख्या दिवस जागरूक करता है कि सुरक्षित भविष्य और भावी पीढ़ियों को बेहतर दुनिया प्रदान करने के लिए हम जनसंख्या विस्फोट जैसी स्थिति से बचें। जनसंख्या की असंतुलित बढ़ोतरी समाज और राष्ट्र के साथ आवश्यक संसाधनों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसके अलावा, कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने विश्व जनसंख्या दिवस पर कहा, देश में जनसंख्या वृद्धि की निरंतर बढ़ती गति न केवल चिंता का विषय है, बल्कि यह हमारे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आइए हम सभी मिलकर जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लें।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा, संतुलित जनसंख्या ही समृद्ध समाज और सतत विकास की सुदृढ़ आधारशिला है। जनसंख्या नियंत्रण आज केवल आवश्यकता नहीं, बल्कि राष्ट्र-निर्माण की अनिवार्य नीति है। यह लक्ष्य जन-जागरूकता, जन-भागीदारी और जननीति के समन्वित प्रयासों से ही प्राप्त हो सकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, तेजी से बढ़ती जनसंख्या हमारे संसाधनों, पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है। आइए, हम सभी जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के महत्व को समझें और समाज को जागरूक कर एक संतुलित एवं सशक्त राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं।

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विश्व जनसंख्या दिवस पर एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि जनसंख्या विस्फोट जैसी स्थिति से बचना जरूरी है। असंतुलित जनसंख्या वृद्धि समाज, राष्ट्र और उपलब्ध संसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। मेघवाल ने अपने संदेश में भावी पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और बेहतर दुनिया सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण न केवल पर्यावरण और संसाधनों के संरक्षण के लिए जरूरी है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है।वहीं, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भारत की विशाल जनसंख्या को देश की ताकत बताया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है और इसमें अपार संभावनाएं छिपी हैं। शिवकुमार ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सभी के लिए समान अवसरों के माध्यम से इस जनसांख्यिकीय लाभ को प्रगति का आधार बनाने की बात कही।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

बिहार चुनावों में महिलाओं पर दांव के निहितार्थ

ललित गर्ग

सरकारी नौकरियों में स्थानीय महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण के गहरे निहितार्थ हैं। एनडीए की नीतिश सरकार ने स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता देने एवं उनके लिए सरकारी रोजगार उपलब्ध कराने के इस ब्रह्मास्त्र को दाग कर चुनावी समीकरण अपने पक्ष में कर लिये हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे 'महिला सशक्तिकरण का राजनीतिक समाधान' बताया, क्योंकि राज्य की महिलाएँ कई चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। पिछली लोकसभा चुनाव में महिलाओं की मतदान दर पुरुषों से कहीं अधिक रही, 59.45 प्रतिशत महिलाओं ने हिस्सा लिया जबकि पुरुष केवल 53 प्रतिशत मतदान करने पहुंचे।

बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने अभी तक मतदान की तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। विभिन्न राजनीतिक दल लुभावनी घोषणाएं कर रहे हैं, नये-नये मुद्दों को उछाला जा रहा है। गोपाल खेमका हत्याकांड हो या तंत्र मंत्र के चलते एक ही परिवार के पांच लोगों को जला देने की त्रासद घटना- नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूचियों के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान पर संदेह के सवालों के साथ मुखर विपक्षी दल इसके खिलाफ राजनीतिक लड़ाई के साथ ही कानून विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इस बीच, एनडीए की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान ने एनडीए से दूरी बनाते हुए बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का संकेत देकर सियासी परिदृश्य को दिलचस्प बना दिया है। इन्हीं परिदृश्यों के बीच बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में स्थानीय महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के फैसला लेकर चुनावी सरगर्मियों को एक नया मोड़ दे दिया है। बिहार सरकार का यह निर्णय केवल एक चुनावी रणनीति भर नहीं, बल्कि एक गहरे सामाजिक परिवर्तन का संकेतक भी है। तय है कि इस बार के बिहार चुनाव के काफी दिलचस्प एवं हंगामेदार होंगे।

सरकारी नौकरियों में स्थानीय महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण के गहरे निहितार्थ हैं। एनडीए की नीतिश सरकार ने स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता देने एवं उनके लिए सरकारी रोजगार उपलब्ध कराने के इस ब्रह्मास्त्र को दाग कर चुनावी समीकरण अपने पक्ष में कर लिये हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे 'महिला सशक्तिकरण का राजनीतिक समाधान' बताया, क्योंकि राज्य की महिलाएँ कई चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। पिछली लोकसभा चुनाव में महिलाओं की मतदान दर पुरुषों से कहीं अधिक रही, 59.45 प्रतिशत महिलाओं ने हिस्सा लिया जबकि पुरुष केवल 53 प्रतिशत मतदान करने पहुंचे। यह आंकड़ा दिखाता है कि चुनावी जीत में महिला मतदाता कितनी निर्णायक हो सकते हैं, साफ है, सत्ता की चाबी वहां महिलाओं ने अपने हाथों में ले ली है और वे धार्मिक व जातिगत आग्रहों से अधिक लैंगिक हितों से प्रेरित हैं। बिहार उन शुरूआती राज्यों में एक है, जिसने पंचायत और स्थानीय निकायों में आधी आबादी के लिए पचास फीसदी सीटें आरक्षित की हैं। इस कदम ने यहां की स्त्रियों में जबर्दस्त राजनीतिक जागरूकता पैदा की है। चुनावों की दशा एवं दिशा बदलने में महत्वपूर्ण एवं निर्णायक किरदार

निभाने के कारण ही हरेक राजनीतिक दल महिला वर्ग को आकर्षित करने में जुट गया है। राजद-कांग्रेस-वाम दलों का महागठबंधन 'माई-बहिन मान योजना' के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये देने का वायदा कर चुका है, तो राजद नेता तेजस्वी यादव बेरोजगारी और डोमिसाइल के मुद्दे को जोर-शोर से उठा रहे हैं। ऐसे में, नीतीश सरकार के इस नीतिगत दांव को समझा जा सकता है। जातिगत और स्थानीय समीकरण भुनाने के लिए निश्चित ही यह एक संगठित चाल है, जहां जाति और आवासीयता दोनों को आधार बनाया गया।

यह सर्वविदित तथ्य है कि भारत में शैक्षिक क्षेत्र में लैंगिक खाई लगातार सिमट रही है। बिहार की बेटियां देश के अनेक महानगरों में अपनी योग्यता और मेहनत के दम पर पहचान बना चुकी हैं। सूचना क्रांति, बढ़ती अपेक्षाओं और सामंती बंधनों के ढीले पड़ते जाने के कारण अब ग्रामीण बिहार की बेटियां भी ऊंचे सपने संजो रही हैं। हाल ही में बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के दौरान यह देखा गया कि देश के विभिन्न प्रदेशों की योग्य लड़कियां इंटरव्यू देने आईं, जिनमें से अनेक ने सफलता प्राप्त की और अब बिहार के सरकारी स्कूलों में अध्यापन कर रही हैं। निस्संदेह, यह एक सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील और समावेशी समाज का प्रतीक है, जहाँ महिलाएं सीमाओं से परे जाकर अपनी पहचान बना रही हैं। लेकिन व्यावहारिक धरातल पर देखें, तो महिला सुरक्षा, सामाजिक असमानता, आवास व पारिवारिक बाधाएं, और प्रवास की मजबूरियाँ अब भी मौजूद हैं। ऐसे में यदि सरकारें योग्य महिलाओं को उनके घर के आस-पास ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं, तो यह न केवल महिला सशक्तिकरण की दिशा में सार्थक कदम होगा, बल्कि सामाजिक संरचना में स्थिरता और पारिवारिक सहूलियत का भी कारण बनेगा। यही कारण है कि नीतीश कुमार सरकार महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए एक के बाद एक योजनाएं ला रही है। साइकिल योजना, पोशाक योजना, कन्या उत्थान योजना, वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि, पिंक टॉयलेट, महिला पुलिस भर्ती में आरक्षण जैसे कई कदम इस सिलसिले में पहले ही उठाए जा चुके हैं। यह मान्यता कि बेटियां अब सिर्फ अपने घरों की शोभा नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की भागीदार हैं, नीति निर्माण में स्पष्ट झलकने लगा है। यह न केवल बिहार की महिलाओं को उनके अधिकार का अनुभव कराएगा, बल्कि बेरोजगारी से जूझते प्रदेश में स्थानीय प्रतिभा के पलायन को भी रोकेगा। इस फैसले से खास तौर पर निम्न और मध्यमवर्गीय महिलाओं को फायदा होगा, जिनके लिए दूसरे शहरों में जाकर नौकरी करना एक बड़ा पारिवारिक और सामाजिक संकट बन जाता है। घर के पास नौकरी मिलने से न केवल सुरक्षा की भावना बढ़ेगी, बल्कि समाज में महिलाओं की स्थायी उपस्थिति और भूमिका भी मजबूत होगी।

हालांकि इस फैसले को लेकर विपक्षी दलों की मिश्रित प्रतिक्रिया सामने आई है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने इसे नीतीश कुमार की चुनावी चाल बताया है और आरोप लगाया है कि सरकार महिलाओं की वास्तविक समस्याओं को दूर नहीं कर पा रही, बल्कि सिर्फ भावनात्मक मुद्दों को उछालकर वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव का कहना है कि 'महिला आरक्षण सही है, लेकिन रोजगार के अवसर कब हैं? सरकारी नियुक्तियों की प्रक्रिया वर्षों से लटकी रहती है, परीक्षा की तारीखें टलती हैं, नियुक्ति पत्र देर से आते हैं, ऐसे में आरक्षण का लाभ कब और किसे मिलेगा?' उनकी बातों में सच्चाई भी है, क्योंकि प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और समयबद्धता भी उतनी ही आवश्यक है जितनी आरक्षण की नीति। यह महिला आरक्षण अब केवल बिहार के स्थायी निवासियों अर्थात डोमिसाइल महिलाओं के लिए ही होगा। यानी जो महिलाएं राज्य की स्थायी निवासी नहीं हैं, उन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा-उन्हें सामान्य श्रेणी में आवेदन करना होगा। इसलिये इसे केवल घरेलू हितों को साधने वाला प्रत्यक्ष प्रचार माना जा रहा है, जिसमें गैर-स्थायी निवासियों को अवसरों से वंचित किया जा रहा है। विपक्ष इस कदम को डोमिसाइल नीति के अनुरूप बताते हुए सवाल उठा रहा है कि क्या इससे सामाजिक न्याय और समान अवसर की भावना नहीं बिगड़ जाएगी?

बिहार में बेरोजगारी चुनावी चर्चा का मुख्य मुद्दा है। युवा खासकर उच्चशिक्षित वर्ग नौकरी की तलाश में है। 35 प्रतिशत आरक्षण के साथ-साथ सरकार ने वेकेंसी क्रिएशन, युवा आयोग गठन, कृषि व सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च जैसे उपाय किए है। 2025 के बिहार चुनाव बहुआयामी लड़ाई से परिपूर्ण है, जातिगत समीकरण, युवा और ग्रामीण विकास, मतदाता सूची संशोधन जैसे मुद्दों ने चुनावी माहौल को गहराई दी है। सरकार ने पिछले बजट में 'महिला हाट', 'पिंक बस', 'पिंक टॉयलेट', स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए साइकिल योजनाएं, दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 'संबल' वित्तीय सहायता जैसी महिलाओं को लुभाने वाली योजनाओं के प्रावधान किये हैं। नीतीश सरकार ने चुनावों को देखते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब वृद्ध, दिव्यांग और विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 400 रुपए की बजाय 1100 रुपए पेंशन मिलेगी। इस घोषणा के बाद पूरे बिहार में पेंशन के 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार लाभार्थियों में हर्ष का माहौल दिखाई दे रहा है। यह कहना उचित होगा कि बिहार की राजनीति इस बार स्थानीयता, जातिगत समीकरण और सामाजिक कल्याण के मिश्रित आरोपणों के बीच गंभीर मुठभेड़ के दौर से गुजर रही है। चुनाव नतीजे यह तय करेंगे कि क्या यह रणनीतियाँ सचमुच सतत परिवर्तन की ठोस बुनियाद रखेंगी, या चुनावी भाषण के बाद हवा में खो जाएँगी। नवीनतम ओपिनियन पोल बताते हैं कि एनडीए फिर सत्ता में लौट सकता है, खासकर महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के बीच मजबूत समर्थन के चलते। वहीं, महागठबंधन (आरजेडी, कांग्रेस, अन्य) जातीय समीकरण (ईबीसी-ओबीसी) का आधार लेकर मुकाबले में है।

संपादकीय

पुनरीक्षण पर हुंकार

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की जरूरत बिहार में ही क्यों पड़ी, वह भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। इसके खिलाफ विपक्ष में विरोध के स्वर तो उठने ही थे। अंतिम एसआईआर, 2003 से अब तक कई विधानसभा और लोक सभा चुनाव हो चुके हैं, क्या चुनाव आयोग को एक बार भी एसआईआर की जरूरत महसूस हुई। कोई साक्ष्य नहीं मिलता। लोक सभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर उंगली उठाते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए 'धांधली' की गई और केंद्र की राजग सरकार इस साल के अंत में होने वाले बिहार चुनावों में भी ऐसा करना चाहती है। उन्होंने साफ कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर के खिलाफ बुधवार को राज्य भर में प्रदर्शन हुए जिसके लिए राहुल सहित विपक्षी महागठबंधन के शीर्ष नेता पटना में एकत्र हुए। हालांकि बुधवार को ही मजदूर संगठनों का श्रम संहिताओं के विरोध में चक्का जाम भी था और इंडिया गठबंधन इसका समर्थन कर रहा था। लेकिन बिहार में उसने एसआईआर के खिलाफ अपनी आपत्तियां उजागर करने को अहमियत दी। आरोप है कि यह प्रक्रिया 'बड़ी संख्या में मतदाताओं को मताधिकार से वंचित' कर देगी जिससे सत्तारूढ़ राजग को लाभ होगा। राहुल ने पटना में निर्वाचन आयोग के कार्यालय तक विरोध मार्च के दौरान कहा विशेष गहन पुनरीक्षण, मतदाता सूची में हेराफेरी के 'महाराष्ट्र मॉड्ल' का विस्तार है, और इससे न केवल लोगों के वोट देने का अधिकार छिनेगा बल्कि उनका भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। उन्होंने निर्वाचन आयोग को संविधान की रक्षा करने की नसीहत देते हुए आरोप लगाया कि वह भाजपा के निदेर्शों पर काम कर रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण चुनावी चोरी का एक प्रयास है। हम निर्वाचन आयोग को मतदाताओं खासकर युवाओं के अधिकार (मतदान के) छीनने नहीं देंगे। आयोग के सदस्यों की चयन प्रक्रिया से प्रधान न्यायाधीश को बाहर कर देने के बाद से इसके कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं। आयोग इनका जवाब देने में कोई तत्परता नहीं दिखाता। भले ही वह सही रास्ते पर हो लेकिन उसका काम विपक्ष को चौंकाना और हलकाना नहीं उसकी आपत्तियों का निस्तारण करना भी है।

चिंतन-मनन

अंतर्दृष्टि से अनुबंधित है ज्ञान

बुद्धि अच्छी चीज है, पर कोरी बौद्धिकता ही सब कुछ नहीं है। इससे व्यक्ति के जीवन में नीरसता और शुष्कता आती है। ज्ञान अंतर्दृष्टि से अनुबंधित है, इसलिए यह अपने साथ सरसता लाता है। ज्ञानी व्यक्तियों के लिए पुस्तकीय अध्ययन की विशेष अपेक्षा नहीं रहती। भगवान महावीर ने कब पढ़ी थीं पुस्तकेंट आचार्य भिक्षु, संत तुलसी, संत कबीर अदि जितने ज्ञानवान पुरुष हुए हैं, उनमें कोई भी पंडित नहीं थे। अंतर्दर्शन उनकी ज्ञानमयी चेतना की स्फुरणा करता था। इसके आधार पर ही उन्होंने गंभीर तत्वों का विश्लेषण किया। वे यदि पुस्तकों के आधार पर प्रतिबोध देते तो संसार को कोई नया दृष्टिकोण नहीं दे सकते थे।

एक बात और ज्ञातव्य है। विद्वान बहुत पढ़े-लिखे होते हैं, पर वे आज तक भी किसी ज्ञानी को पराजित नहीं कर सके। इंद्रभूति महापंडित थे। उनका पांडित्य विश्रुत था। पर वे भगवान महावीर की ज्ञान चेतना का अनुभव करते ही पराभूत हो गए। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। ज्ञान और बुद्धि की परस्पर कोई तुलना नहीं है। बुद्धि कुंड का पानी है और ज्ञान कुएं का पानी है। कुंड का पानी जितना है उतना ही रहता है। वर्षा होती है तो पानी थोड़ा बढ़ जाता है। इसी प्रकार अनुकूल सामग्री और पुरुषार्थ का योग होता है तो बुद्धि बढ़ जाती है। अन्यथा उसके विकास की कोई संभावना नहीं रहती। कुएं से जितना पानी निकाला जाता है, नीचे से और आता रहता है। वह कभी चुकता नहीं है, उसमें नए अनुभव जुड़ते जाते हैं।

बुद्धि आवश्यक है किंतु उसके आधार पर कभी आत्म-दर्शन नहीं हो पाता। आत्म-दर्शन का पथ है ज्ञान। ज्ञान तब तक उपलब्ध नहीं होता जब तक ध्यान का अभ्यास न हो। जिस व्यक्ति को अंतर्दृष्टि का उद्घाटन करना है, ज्ञानी बनना है, उसे प्रेक्षाध्यान साधना का आलंबन स्वीकार करना होगा। ऐसा करके वह ज्ञान की श्रेष्ठता को प्रमाणित कर सकता है।

परीक्षा प्रणाली या सामाजिक भ्रमजाल?

सोनम लवंशी

शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला कहा गया है। यह व्यक्ति के ज्ञान, विवेक, सृजनात्मकता और व्यक्तित्व विकास का माध्यम रही है। लेकिन आज की तारीख में यह उद्देश्य कहीं पीछे छूट गया है। शिक्षा अब एक ह्यअंक-उद्योगह्ल में तब्दील हो चुकी है, जहां ज्ञान की बजाय नंबर ही सफलता का पर्याय बन गए हैं। अब यह न तो चरित्र निर्माण का साधन रही, न ही सामाजिक चेतना का उपकरण। यह छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को अंक-दौड़ की एक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा में धकेलने वाला शोषण तंत्र बन गई है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में इस बार 45,516 छात्रों ने 95 फीसदी से ज्यादा अंक प्राप्त किए, जो कुल परीक्षार्थियों का लगभग 1.92 प्रतिशत है। वहीं 1,99,944 छात्रों ने 90 फीसदी से ज्यादा अंक हासिल किए, जो 8.43 प्रतिशत के करीब है। यह कोई अपवाद नहीं है हर साल यह आंकड़ा और ऊपर जा रहा है। लेकिन जब इन अंकों की असलियत जानने के लिए उत्तर पुस्तिकाएं जांचने वाले शिक्षकों की कार्यप्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली पर सवाल उठते हैं, तो व्यवस्था मौन हो जाती है। यह एक साजिशन खड़ा किया गया भ्रमजाल है, जो शिक्षा को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की बजाय एक कृत्रिम दौड़ में तब्दील कर रहा है।

शिक्षा के इस व्यवसायीकरण की गहराई को समझने के लिए जरूरी है कि हम उस ढांचे को देखें जिसमें यह सब संचालित हो रहा है। 2019 में सीबीएसई से मान्यता प्राप्त कुल 22,030 स्कूलों में से लगभग 80 प्रतिशत स्कूल निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस आंकड़े में केवल 1,138 केंद्रीय विद्यालय, 2,727 सरकारी स्कूल, 598 नवोदय विद्यालय और 14 तिब्बती स्कूल शामिल हैं, जबकि शेष 17,553 निजी स्कूल हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा निजीकरण के दबाव में है, जहां शिक्षा की गुणवत्ता नहीं, बल्कि परिणामों की संख्या मायने रखती है और जब यही ह्यअंकवीरह्ल छात्र राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, जेईई या नीट में पहुंचते हैं, तो उनकी वास्तविक योग्यता सामने आ जाती है। उदाहरण के लिए, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2019 में लगभग 11.35 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से मात्र 11,474 छात्र ही मुख्य परीक्षा तक पहुंच सके। यही हाल साल 2024 का रहा। इस वर्ष लगभग 13.4 लाख छात्रों में से सिर्फ 14,627 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा तक पहुंचे। यानि बोर्ड परीक्षा के हाई स्कोरर प्रीलिम्स की पहली कसौटी पर ही फेल हो जाते हैं। यह दशार्ता है कि बोर्ड परीक्षाओं में मिलने वाले ऊंचे अंक असल में बौद्धिक क्षमता या विषय की समझ का पैमाना नहीं हैं। यह मूल्यांकन प्रणाली रटंत विद्या, तयशुदा उत्तरों और सजावटी भाषा पर आधारित है, जिसमें मौलिक सोच और विश्लेषण की कोई जगह नहीं।

यह समस्या केवल स्कूली शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिकता पूरे उत्तर भारत के शैक्षणिक वातावरण में व्याप्त है। स्कूलों में अब शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान देना नहीं, बल्कि अच्छे परिणामों के जरिए स्कूल का नाम रौशन करना बन गया है। इसके उलट, दक्षिण भारत की तस्वीर अपेक्षाकृत बेहतर है। वहां के माता-पिता शिक्षा को केवल अंक पाने के माध्यम के रूप में नहीं, बल्कि व्यक्तित्व विकास और कौशल निर्माण के रूप में देखते हैं। यही कारण है कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों के छात्र राष्ट्रीय परीक्षाओं में निरंतर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। वहां की शिक्षा प्रणाली में केवल परीक्षाफल नहीं, बल्कि सोचने-समझने की क्षमता, व्यवहारिकता और नवाचार को भी महत्व दिया जाता है। उत्तर भारत के अधिकतर स्कूलों में शिक्षण अब गाइडबुक, मॉडल पेपर और स्मार्ट आंसर पर आधारित हो गया है। शिक्षक भी केवल परिणाम उन्मुख होकर पढ़ाते हैं, क्योंकि उनके मूल्यांकन का आधार भी अब बच्चों के अंक बन गए हैं। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम बच्चों की मानसिक स्थिति पर पड़ता है। नंबर की होड़ में बच्चों में अवसाद, आत्महत्या की प्रवृत्ति, हीन भावना और मानसिक तनाव बढ़ रहा है। शिक्षा अब ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि एक दौड़ बन गई है, जिसमें सबसे तेज दौड़ने वाला ही विजेता माना जाता है। यहां तक की कोचिंग टाउन बन चुके शहर कोटा, दिल्ली, पटना, प्रयागराज और इंदौर इस अंक-उद्योग की सबसे बड़ी मिसाल हैं। यहां छोटे-छोटे बच्चों से लेकर स्नातक विद्यार्थी तक ह्यरैंक मशीनह्ल बनने के लिए दिन-रात खप रहे हैं। यह एक सामाजिक दबाव का परिणाम है, जो विशेष रूप से उत्तर भारत में डॉक्टर-इंजीनियर बनने की लीक पर चलता है। वहीं दक्षिण भारत में शिक्षा के विविध विकल्पों, व्यावसायिक दक्षता और कौशल विकास को भी उतना ही महत्व मिलता है। यह सोच का फर्क है, जो वहां के छात्रों को तकनीकी और प्रशासनिक क्षेत्रों में मजबूत बनाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस अंक-उद्योग की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह छात्रों के भीतर सोचने, सवाल उठाने और नवाचार की प्रवृत्ति को कुचल देता है। शिक्षा का उद्देश्य विवेक, तर्क और संदेह की भावना का विकास था, पर अब यह केवल स्मृति और दोहराव पर आधारित हो गया है। मीडिया में टॉपर बच्चों के साक्षात्कार इस मानसिकता को और पुष्ट करते हैं, जहां दिन में 16 घंटे पढ़ना, दस साल के पेपर रटना और कई-कई किताबें घोंटना ही सफलता का मंत्र बताया जाता है। यह विचारणीय है कि क्या वास्तव में यही शिक्षा है?

इस समस्या का समाधान केवल परीक्षा प्रणाली बदल देने से नहीं होगा। जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, तब तक शिक्षा का यह विकृत रूप बना रहेगा। जब तक अभिभावक अंक को ही सफलता की कसौटी मानते रहेंगे, स्कूलों और शिक्षकों की प्राथमिकता भी वहीं रहेगी। जरूरत है एक नई शैक्षणिक संस्कृति की जहां असफलता को अवसर माना जाए, बच्चों की विविधता को अपनाया जाए और उन्हें आत्मविश्लेषण और आत्म-अनुशासन के मार्ग पर प्रेरित किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस दिशा में कुछ सकारात्मक पहलें की हैं, परंतु इन्हें जमीन पर लागू करना एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है। अब समय है कि हम स्कूलों को रैंक उत्पादक मशीनों से बाहर निकालें। अभिभावकों को समझना होगा कि उनका बच्चा कोई अंकों का रिपोर्ट कार्ड नहीं, बल्कि एक सोचने, समझने और विकसित होने वाली मनुष्य-प्रवृत्ति है।

धर्मांतरण का धंधा: विदेशी फंडिंग और सामाजिक विघटन का षड्यंत्र

डॉ. सत्यवान सौरभ

उत्तर प्रदेश में एटीएस ने एक बड़े धर्मांतरण रैकेट का खुलासा किया है, जिसमें विदेशी फंडिंग के जरिए करीब 100 करोड़ रुपये 40 खातों में भेजे गए। मुख्य आरोपी 'छांगरू बाबा' उर्फ जमशेदुद्दीन के नेतृत्व में यह गिरोह ऊंची जाति की लड़कियों के लिए 15-16 लाख रुपये की दर से धर्मांतरण कराता था। यह मामला केवल आस्था नहीं, बल्कि एक सुनियोजित सामाजिक षड्यंत्र है जो जाति, धर्म और लिंग के आधार पर राष्ट्र की एकता को तोड़ने का प्रयास करता है। इसे धार्मिक स्वतंत्रता नहीं, संगठित अपराध के रूप में देखा जाना चाहिए।

धर्म किसी भी समाज की आत्मा होता है, लेकिन जब धर्म का प्रयोग धंधे में बदल जाए तो सवाल सिर्फ आस्था का नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा, सामाजिक समरसता और नैतिक मूल्यों का हो जाता है। उत्तर प्रदेश में एटीएस द्वारा उजागर किए गए एक बड़े धर्मांतरण रैकेट ने यही भयावह सच्चाई हमारे सामने रखी है। कथित रूप से छांगरू बाबा उर्फ जमशेदुद्दीन के नेतृत्व में यह गिरोह न केवल भोले-भाले लोगों का धर्मांतरण कर रहा था, बल्कि इसके पीछे एक व्यवस्थित नेटवर्क, विदेशी फंडिंग और जातिगत लक्ष्य निर्धारण भी शामिल था।

जिस प्रकार से इस रैकेट की कार्यप्रणाली सामने आई है, वह धर्मांतरण को एक सुनियोजित व्यवसाय के रूप में प्रकट करती है। यह कोई व्यक्तिगत आस्था का निर्णय नहीं, बल्कि विदेशी पैसों से संचालित एक मिशन था - जिसमें धर्म, जाति, स्त्री और समाज को एक वस्तु की तरह देखा गया। एफआईआर और जांच रिपोर्ट के अनुसार, धर्मांतरण के लिए बाकायदा रेट कार्ड था। ऊंची जाति की लड़कियों के लिए धर्मांतरण की दर 15-16 लाख रुपये तक थी, जबकि अन्य लड़कियों के लिए 8-10 लाख रुपये। सोचिए, जब धर्म को भी जाति और लिंग के आधार पर मूल्यांकित किया जाने लगे, तो वह किस स्तर तक गिरावट का प्रतीक बनता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस रैकेट के पास 40 बैंक खाते थे जिनमें विदेशों से 100 करोड़ रुपये से अधिक की रकम भेजी गई। यह रकम किसके इशारे पर भेजी गई, किन उद्देश्यों के लिए, और किन देशों से ह्य यह सवाल सिर्फ जांच एजेंसियों के नहीं, पूरे देश के हैं। क्या यह केवल धर्मांतरण के लिए था या इसके पीछे कोई और बड़ा वैश्विक, राजनीतिक या वैचारिक षड्यंत्र भी छिपा है?

इस रैकेट की कार्यशैली में सोशल मीडिया का जबरदस्त उपयोग किया गया। वीडियो, मोटिवेशनल भाषण, 'इस्लाम कबूल करने से मिली राहत' जैसे फर्जी वीडियो वायरल कर कमजोर तबकों को बरगलाया गया। पहले मानसिक रूप से प्रभावित किया गया, फिर आर्थिक लालच दिया गया और अंत में जबरन धर्मांतरण। यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जैसा है ह्य जहां पहले मस्तिष्क जीता जाता है, फिर शरीर। और सबसे दुखद यह कि इसे धर्म का नाम दिया गया।

इस प्रकरण में बलरामपुर जिले के एक पूरे परिवार के धर्मांतरण की पुष्टि हुई है। वहां महिलाओं और बच्चों को टारगेट कर उन्हें धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया। यह कोई एक अपवाद नहीं, बल्कि उसी पैटर्न का हिस्सा है ह्य जिसमें ग्रामीण, अशिक्षित और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को निशाना बनाया जाता है। यह सामाजिक असमानता का शोषण है। जब राज्य, समाज और प्रशासन इन परिवारों की रक्षा नहीं कर पाते, तो ऐसे गिरोह अपना मकड़जाल फैलाते हैं। इस रैकेट का सबसे खतरनाक पहलू था - जातिगत दर निर्धारण। ऊंची जाति की लड़कियों के धर्मांतरण के लिए अधिक पैसा दिया जाता था। इसका मतलब है कि धर्मांतरण सिर्फ धर्म का नहीं, जाति-सामाजिक संरचना को तोड़ने का औजार भी बन चुका है। यह न केवल हिंदू समाज को कमजोर करने की चाल है, बल्कि राष्ट्र को आंतरिक रूप से विखंडित करने की भी रणनीति है।

इस मामले पर तथाकथित सेक्युलर बुद्धिजीवी वर्ग चुप है। वही वर्ग जो 'धर्मनिरपेक्षता' की दुहाई देता है, 'संविधान की आत्मा' की बात करता है, आज गूंगा बना बैठा है। क्यों? क्या धर्मांतरण को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मान लिया गया है? क्या किसी गरीब, दलित, महिला या आदिवासी का जबरन धर्म बदलवाना मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है? अगर किसी दलित के मंदिर में प्रवेश करने से किसी को आपत्ति है, तो उस पर शोर मचता है, लेकिन जब उसी दलित को पैसों से धर्म बदलवाया जाता है तो कोई नहीं बोलता। यह मौन स्वयं एक अपराध है।

यह भी गौरतलब है कि ऐसे मामलों पर राजनीतिक दल अक्सर वोट बैंक की राजनीति के कारण खुलकर प्रतिक्रिया नहीं देते। अल्पसंख्यकों की 'संवेदनशीलता' के नाम पर ऐसे राष्ट्रघातक कृत्यों को नजरअंदाज किया जाता है। सवाल यह है कि क्या देश की अखंडता और सामाजिक समरसता वोट बैंक से भी छोटी हो गई है? अगर कोई हिंदू संगठन धर्मांतरण रोकने की बात करता है तो उसे कट्टरपंथी कह दिया जाता है, लेकिन जब धर्मांतरण के नाम पर विदेशी पैसा आकर समाज को तोड़ता है, तो सब चुप हो जाते हैं।

यह मामला अकेला नहीं है। देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो सामाजिक दुर्बलता, आर्थिक मजबूरी और शिक्षा की कमी का लाभ उठाकर धर्मांतरण करा रहे हैं। इससे निपटने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानूनों को और मजबूत बनाना चाहिए। विदेशी फंडिंग की निगरानी के लिए डिजिटल ट्रैकिंग तंत्र को सशक्त करना चाहिए। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा और रोजगार के माध्यम से समाज को आत्मनिर्भर और सजग बनाना जरूरी है।

धर्म आत्मा का विषय है, उसे सौदेबाजी का औजार बनाना न केवल अपराध है, बल्कि मानवता का भी अपमान है। धर्मांतरण जब व्यक्तिगत चेतना से नहीं, लालच, भय या फरेब से होता है, तो वह धर्म नहीं, शोषण होता है। हमारे लिए जरूरी है कि हम धर्मांतरण की आड़ में चल रहे इन संगठित अपराधों को पहचानें, उनका विरोध करें और समाज को ऐसी गतिविधियों से बचाने के लिए संगठित प्रयास करें। धर्म को न बेचे, न खरीदें ह्य बल्कि समझें, आत्मसात करें और उसकी गरिमा को बचाए रखें।

(स्वतंत्र पत्रकार व स्तंभकार)

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

अलाइड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड ने सेबी के पास डीआरएचपी दाखिल किया

मुंबई, एजेंसी। टेक्नोलॉजी-ड्रिवन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर कंपनी अलाइड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड ने मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल कर दिया है। यह कंपनी पूरे भारत में स्मार्ट मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लागू करने और यूटिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यूटिलिटीज की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने पर फोकस करती है। कंपनी आईपीओ के जरिये इक्विटी शेयर के पिटल ऑफर करके फंड जुटाने की प्लानिंग कर रही है। इस इश्यू में ?4,000 मिलियन (?400 करोड़) तक के नए इक्विटी शेयरों का फ्रेश इश्यू और ?5 फेस वैल्यू वाले 7,500,000 इक्विटी शेयरों तक का ऑफर फॉर सेल शामिल है। 31 मार्च, 2025 तक 7.29 मिलियन एनर्जी मीटर प्रति वर्ष की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के मामले में अलाइड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड भारत की टॉप पांच एनर्जी मीटर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर्स में से एक है (सोर्स- क्रिसिल रिपोर्ट)। कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ के मामले में भारत की सबसे तेजी से बढ़ती कॉम्प्रिहेंसिव स्मार्ट एनर्जी मीटर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर भी है, जिसने वित्त वर्ष 2023 से वित्त वर्ष 2025 तक 109.76त्न की ष्ट्रक्र हासिल की है (सोर्स- क्रिसिल रिपोर्ट)। कंपनी कम्युनिकेशन नेटवर्क और डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म सहित सपोर्टिंग टेक्नोलॉजीज के साथ-साथ स्मार्ट एनर्जी मीटर की एक रेंज का निर्माण और आपूर्ति करती है।

अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय ने डेवेलपमेंट मैनेजमेंट में एक्ज़ीक्यूटिव एमबीए की घोषणा की

इंदौर, एजेंसी। अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय ने डेवेलपमेंट मैनेजमेंट में एक्ज़ीक्यूटिव एमबीए कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की है। यह एक वर्षीय पूर्णकालिक स्नातकोत्तर कार्यक्रम विशेष रूप से कार्यरत पेशेवरों के लिए तैयार किया गया है। इसका पहला बैच जनवरी 2026 में विश्वविद्यालय के बेंगलुरु परिसर में आरंभ होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 है। यह कार्यक्रम प्रबंधन शिक्षा की बढ़ती माँग को पूरा करता है जो लाभ और प्रदर्शन से आगे बढ़कर समाज की आवश्यकताओं को केंद्र में रखकर प्रबंधन शिक्षा की अपेक्षा करती है। पारंपरिक एमबीए कार्यक्रमों से अलग, यह पाठ्यक्रम पेशेवरों को सामाजिक परिवर्तन, सार्वजनिक हित और समावेशी विकास पर केंद्रित संस्थाओं में प्रभावशाली योगदान देने के लिए तैयार करता है। पाठ्यक्रम में वित्त, मानव संसाधन प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, और संगठनात्मक संरचना जैसे मुख्य प्रबंधन विषयों के साथ-साथ विकास कार्य के व्यावहारिक पहलुओं का गहरा समावेश है।

मॉनसून में आयुर्वेद डाइट से कुदरती रूप से दमकती, सेहतमंद त्वचा पाएं : डॉ मधुमिता कृष्णन

नई दिल्ली, एजेंसी। मॉनसून में त्वचा बेजान हो जाती है और इसमें कोई ग?लो नहीं दिखता। लोग अक्सर बाहरी उपाय अपनाते हैं, जो थोड़ी देर राहत देते हैं, लेकिन बार-बार इस्तेमाल से दाने, काले धब्बे या खुजली हो सकती है। आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. मधुमिता कृष्णन सलाह देती हैं कि त्वचा और पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक तरीके अपनाएं। वे कहती हैं कि स्वस्थ खाना खाएं और बादाम, हर्बल चाय और हल्दी जैसे प्राकृतिक चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें। आयुर्वेद के मुताबिक, सही खानपान शरीर के तीन दोषों-वात, पित्त और कफ-को संतुलित करता है, जिससे त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनती है, क्योंकि अच्छी त्वचा के लिए अच्छा पाचन जरूरी है। बादाम को डाइट में शामिल करें- बादाम वात दोष को संतुलित करने की क्षमता रखते हैं। यह मौसम के असंतुलन को ठीक करते हैं और शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं, जिससे सभी ऊतकों को ऊर्जा और ताजगी मिलती है। आयुर्वेद की पारंपरिक तैयारियों में बादाम का महत्वपूर्ण स्थान है, जो पूरे भारत में लोग अपनाते हैं। त्वचा के स्वास्थ्य के लिए, डॉ. मधुमिता रोजाना नाश्ते में बादाम शामिल करने की सलाह देती हैं ताकि स्वस्थ, चमकदार त्वचा मिले।

इक्विटी फंड में पांच माह की गिरावट थमी निवेश 24% बढ़कर 23587 करोड़

नई दिल्ली, एजेंसी। मजबूत खुदरा भागीदारी और निवेशक अधिक रिटर्न की तलाश में सोने और चांदी के फंडों की ओर निवेश का रुख कर रहे थे। इससे निफ्टी-50 जून में तीन फीसदी बढ़ गया। स्मॉलकैप व मिडकैप में क्रमश- 6.7त्न और 4त्न की वृद्धि हुई।

इक्विटी म्यूचुअल फंडों में पांच महीने से जारी गिरावट थम गई। जून में शुद्ध निवेश 24 प्रतिशत बढ़कर 23,587 करोड़ रुपये हो गया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एम्फी के आंकड़ों के मुताबिक, लगातार 52वें महीने निवेश आया है।

म्यूचुअल फंड में जून में कुल 49,301 करोड़ रुपये का निवेश आया, जो मई के 29,572 करोड़ रुपये की तुलना में 67 फीसदी ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक, इक्विटी म्यूचुअल फंडों में मई में 19,013 करोड़ रुपये का निवेश आया था। शुद्ध निवेश दिसंबर में 41,156 करोड़ रुपये से घटकर जनवरी में 39,688 करोड़ रुपये, फरवरी में 29,303 करोड़ रुपये, मार्च में 25,082 करोड़ रुपये और अप्रैल में 24,269 करोड़ रुपये रहा था। नवंबर में यह 35,943 करोड़ रुपये था। डेट फंडों में से जून में 1,711 करोड़ रुपये की निकासी हुई। मई में 15,908 करोड़ निकाले गए थे। अप्रैल में कुल 2.2 लाख करोड़ का निवेश आया था।

म्यूचुअल फंड में निवेशकों के निवेश का मूल्य(एयूएम) जून में रिकॉर्ड 74.4 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो मई में 72.2 लाख करोड़ था। इक्विटी फंडों में सबसे अधिक फ्लैक्सी कैप में 5,733 करोड़ का निवेश आया। इक्विटी-लिंक्ड बचत योजनाएं (ईएलएसएस) एकमात्र ऐसी श्रेणी रही जिसमें 556 करोड़ की निकासी हुई।

शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में सबसे अधिक 10,276 करोड़ रुपये का निवेश हुआ। मनी मार्केट फंड्स में 9,484 करोड़ का निवेश हुआ। डायनॉमिक बॉन्ड फंड्स में सबसे कम 44 करोड़ रुपये आए।

लिक्विड फंड से सबसे ज्यादा निकासी लिक्विड फंडों से जून में सबसे अधिक 25,196 करोड़ रुपये निकाले गए। मई में 40,205 करोड़ रुपये की निकासी हुई थी। ओवरनाइट फंडों से 8,154 करोड़ रुपये, मध्यम अवधि के फंडों से सबसे कम 60.98 करोड़ रुपये की निकासी हुई।

व्यवस्थित निवेश योजनाओं (एसआईपी) में रिकॉर्ड 27,269 करोड़ रुपये का निवेश आया। खातों की संख्या मई के 8.56 करोड़ से बढ़कर जून में 8.64 करोड़ हो गई। निवेशकों के निवेश का मूल्य मई की तुलना में 20.2 प्रतिशत बढ़कर 15.31 लाख करोड़ हो गया।

मजबूत खुदरा भागीदारी और निवेशक अधिक रिटर्न की तलाश में सोने और चांदी के फंडों की ओर निवेश का रुख कर रहे थे। इससे निफ्टी-50 जून में तीन फीसदी बढ़ गया। स्मॉलकैप व मिडकैप में क्रमश- 6.7 प्रतिशत और 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

भारतीय स्टेट बैंक शेयरों की बिक्री कर 25000 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में, रिपोर्ट्स में दावा

नई दिल्ली, एजेंसी। संपत्ति के लिहाज से देश का सबसे बड़ा ऋणदाता, भारतीय स्टेट बैंक, अगले हफ्ते संस्थागत क्यूआईपी के जरिए निवेशकों को 25,000 करोड़ रुपये (2.9 अरब डॉलर) के शेयर बेचने की तैयारी कर रहा है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। संपत्ति के लिहाज से देश का सबसे बड़ा ऋणदाता, भारतीय स्टेट बैंक, अगले हफ्ते संस्थागत क्यूआईपी के जरिए निवेशकों को 25,000 करोड़ रुपये (2.9 अरब डॉलर) के शेयर बेचने की तैयारी कर रहा है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के अनुसार यह देश का अपनी तरह का सबसे बड़ा सौदा हो सकता है।

ब्लूमबर्ग की ओर से इकट्ठा किए गए आंकड़ों के अनुसार, अगर योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाता है, तो यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा क्यूआईपी होगा। यह 2015 में कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से की गई 225.6 अरब रुपये की बिक्री से भी आगे निकल जाएगा। बैंक के बोर्ड ने मई में इस बिक्री को मंजूरी दी थी।

सूत्रों के अनुसार, योजनाएं अभी अंतिम रूप नहीं ले पाई हैं और इनमें बदलाव हो सकते हैं। इस मामले में एसबीआई की ओर से फिलहाल कोई बयान जारी नहीं किया गया है। सूत्रों के अनुसार यह बिक्री एसबीआई की ऋण वृद्धि को बढ़ावा देने, अपनी बैलेंस शीट को मज़बूत करने और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने की व्यापक योजनाओं का हिस्सा है।

ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में ईडी सख्त, विजय देवरकोंडा व प्रकाश राज समेत 29 अभिनेताओं-यूट्यूबर्स पर केस

नई दिल्ली, एजेंसी। ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत तेलंगाना में विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबाती और प्रकाश राज जैसे अभिनेताओं के अलावा कुछ सोशल मीडिया के प्रभावशाली लोगों और यूट्यूबर्स की भूमिका की जांच के लिए धन शोधन का मामला दर्ज किया है। आइए इस बारे में जानें।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कुछ ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत बड़ी कार्रवाई की है। तेलंगाना में विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबाती और प्रकाश राज जैसे अभिनेताओं के अलावा कुछ सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स व यूट्यूबर्स सहित दो दर्जन से अधिक लोगों भूमिका की पड़ताल के लिए धन शोधन का मामला दर्ज किया गया है।

सूत्रों ने बताया कि इन दुकानों पर अवैध सट्टेबाजी और जुए के जरिए करोड़ों रुपये की अवैध धनराशि अर्जित करने का आरोप है। उन्होंने बताया कि संघीय जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज करने के लिए पांच राज्य पुलिस प्राथमिकियों का संज्ञान लिया है।

ईडी मामले में देवरकोंडा, दग्गुबाती, मांचू लक्ष्मी, राज, निधि अग्रवाल, प्रणिता सुभाष, अनन्या नागल्ला, टीवी होस्ट श्रीमुखी के अलावा स्थानीय सोशल मीडिया प्रभावितों और यूट्यूबर्स सहित लगभग 29 हस्तियों पर मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों ने बताया कि इन हस्तियों पर सेलिब्रिटी या विज्ञापन शुल्क प्राप्त करने के बदले जंगली रम्मी, जीतविन, लोटस 365 आदि जैसे ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स का समर्थन करने का संदेह है।

सूत्रों ने बताया कि इनमें से कुछ जाने-माने व्यक्तियों ने पहले कहा था कि उन्हें उनके द्वारा पेश किए गए ऐप्स और उत्पादों की सटीक कार्यप्रणाली की जानकारी नहीं थी और उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सट्टेबाजी जैसी किसी भी गलत गतिविधि या अवैध गतिविधि के लिए इन प्लेटफार्मों के साथ खुद को नहीं जोड़ा।

आईपीओ बाजार में हलचल, 70 कंपनियों का 1.60 लाख करोड़ जुटाने का प्लान; निवेशकों की जबरदस्त दिलचस्पी

नई दिल्ली, एजेंसी। इस साल आईपीओ बाजार में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक 70 कंपनियों ने सेबी में मसौदा जमा कर 1.60 लाख करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है। मीशो, पाइन लैब्स जैसे बड़े ब्रांड्स शामिल हैं। वहीं क्रायोजनिक ओजीएस को 17.77 करोड़ के लक्ष्य पर 8,220 करोड़ की रिकॉर्ड बोली मिली है।

चालू वित्त वर्ष में अब तक कुल 70 कंपनियों ने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आईपीओ लाने के लिए बाजार नियामक सेबी के पास मसौदा जमा कराया है। जबकि जनवरी से कुल 120 कंपनियों ने मसौदा जमा कराया है। यह सभी मिलकर 1.60 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जुटाएंगी। कंपनियों को मसौदा जमा कराने के एक साल के भीतर आईपीओ लाना होता है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के मुताबिक, अप्रैल में 24 कंपनियों ने मसौदा जमा कराया। मई में 17, जून में 18 और जुलाई में 14 ने मसौदा जमा कराया। मीशो 4,250 करोड़, पाइन लैब 6,000 करोड़, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड 10,000 करोड़ और क्रेडिला 5,000 करोड़ रुपये जुटाएगी। इस साल 26 कंपनियों ने बाजार से 48,234 करोड़ जुटाए हैं।

गुजरात की क्रायोजनिक ओजीएस के इश्यू में निवेशकों ने 8,220 करोड़ रुपये की बोली लगाई है जबकि कंपनी को केवल 17.77 करोड़ जुटाने थे।

भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश में, फिर वाशिंगटन दौरे पर जाएगी टीम

नई दिल्ली, एजेंसी। अमेरिका के साथ टैरिफ पर एक और दौर की वार्ता के लिए भारतीय टीम जल्द ही वाशिंगटन का दौरा करेगी। सरकार से जुड़े एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। उधर, वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव राजेश अग्रवाल ने गुरुवार को कहा कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत करने और उसे अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहा है। आइए इस बारे में विस्तार से जानें।

अमेरिका के साथ टैरिफ पर एक और दौर की वार्ता के लिए भारतीय टीम जल्द ही वाशिंगटन का दौरा करेगी। सरकार से जुड़े एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। उधर, वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव राजेश अग्रवाल ने गुरुवार को कहा कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत करने और उसे अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहा है।

अग्रवाल प्रस्तावित भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के मुख्य वार्ताकार भी हैं। इस समझौते के पहले चरण को इस साल की शरद ऋतु (सितंबर-अक्तूबर) तक पूरा करने का लक्ष्य है। इससे पहले, दोनों देश एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश हो रही है। अग्रवाल ने कहा कि भारत ने अब तक 26 देशों के साथ 14 से अधिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) लागू किए हैं।

उन्होंने यहां निर्यात लॉजिस्टिक्स पर

आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, अब हम प्रमुख बाजारों के साथ भी एकीकरण कर रहे हैं...हमने हाल ही में ब्रिटेन के साथ एक समझौता किया है, हम यूरोपीय संघ के साथ बातचीत के अग्रिम चरण में हैं, हम अमेरिका के साथ भी समझौते पर बातचीत कर उसे अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत चिली और पेरू सहित लैटिन अमेरिकी देशों के साथ व्यापार समझौतों पर भी बातचीत कर रहा है।

छोटे चाय उत्पादकों ने की एमएसपी जैसी व्यवस्था की मांग, कहा- हो मूल्य निर्धारण में सुधार

नई दिल्ली, एजेंसी। छोटे चाय उत्पादकों ने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) जैसे व्यवस्था की मांग की है। वे पुरानी मूल्य प्राप्ति चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जिससे उन्हें लागत से कम कीमत मिल रही है। उन्होंने इस मांग को लेकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को एक पत्र लिखा है।

देश के छोटे चाय उत्पादकों ने निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्य निर्धारण तंत्र स्थापित करने की मांग की है। इससे उन्हें पत्तियों को बेचकर उचित मूल्य मिलेगा। यह छोटे उत्पादक देश के चाय उत्पादन में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान देते हैं।

इस मांग को लेकर उन्होंने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को एक पत्र लिखा। पत्र में भारतीय लघु चाय उत्पादक संघों के परिसंघ (सीआईएसटीए) ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत मूल्य संरक्षण योजना का सुझाव दिया है। इसमें कहा गया कि चाय बोर्ड को छोटे उत्पादकों और कारखानों के बीच समान मूल्य-साझाकरण अनुपात निर्धारित करने के लिए गहरा अध्ययन करना चाहिए।

सीआईएसटीए के अध्यक्ष बिजॉय गोपाल चक्रवर्ती ने कहा कि छोटे उत्पादकों को लगातार कम कीमत की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इससे इस क्षेत्र की स्थिरता को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि छोटे उत्पादक देश के चाय उत्पादन में 52 प्रतिशत से अधिक का योगदान करते हैं, और उचित मूल्य प्राप्ति तंत्र होना चाहिए ताकि आजीविका बनी रहे।चक्रवर्ती ने कहा कि एसोसिएशन ने मई 2023 में ही वाणिज्य मंत्रालय को एक विस्तृत स्थिति पत्र प्रस्तुत किया था। जिसमें इस क्षेत्र के सामने आने वाली संरचनात्मक बाधाओं को रेखांकित किया गया है, जो पुरानी मूल्य प्राप्ति चुनौतियों से जूझ रहा है।

उन्होंने कहा कि न्यूनतम बेंचमार्क मूल्य की अवधारणा को कुल बिक्री मूल्य से जुड़ी एक नई पद्धति से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। इससे उत्पादकों को उचित और लाभकारी मूल्य प्राप्त होगा। सीआईएसटीए ने श्रीलंकाई मॉडल का समर्थन किया है। इसके तहत नीलामी औसत से अधिक अधिशेष आय को कारखानों और उत्पादकों के बीच समान रूप से बांटा जाता है।

छोटे उत्पादकों के लिए मूल्य संरक्षण योजना का प्रस्ताव करते हुए, इसमें कहा गया है कि वर्तमान में हरी पत्तियों की औसत कीमत 22 रुपये से 25 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच है। वहीं उत्पादन लागत 17 रुपये से 20 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच है। चक्रवर्ती ने कहा कि मामूली मार्जिन पर उत्पादकों को 5 रुपये प्रति किलोग्राम की उपज प्राप्त होती है। दूसरी ओर, एजेंट आमतौर पर 2 रुपये प्रति किलोग्राम लेते हैं। सीआईएसटीए ने कहा कि यह एक बड़ी बाधा है और उत्पादक सीधे कारखानों को बेचने में सक्षम होने चाहिए।

चार ट्रिलियन डॉलर की पहली कंपनी बनी एनवीडिया, टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित पहली बार्बी बाजार में आई

नई दिल्ली, एजेंसी। सिलिकॉन वैली की चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया बुधवार को दुनिया की पहली सार्वजनिक कंपनी बन गई, जिसका मूल्यांकन चार ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो गया है। एनवीडिया ने यह उपलब्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के कारण हासिल की है। इसकी खास चिप्स एआई तकनीक में बहुत काम आती हैं, और दुनियाभर में इनकी मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। प्रौद्योगिकी में ये बदलाव वैसे ही बड़े माने जा रहे हैं, जैसे एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने 18 साल पहले आईफोन लॉन्च करके दुनिया की टेक्नोलॉजी को बदल दिया था। इन बदलावों के चलते एआई क्षेत्र की अग्रणी कंपनी एनवीडिया का मूल्य अब एप्पल से 900 बिलियन डॉलर अधिक है। एप्पल आईफोन की सफलता के बल पर 1, 2 और अंततः 3 ट्रिलियन डॉलर के मूल्यांकन वाली पहली सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बनी थी।

मैटल ने अपनी एक नई बार्बी पेश की है, जो टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। कंपनी का यह कदम अपनी गुड़ियाओं में विविधता और समावेश बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा है। मैटल ने मंगलवार को कहा कि इस गुड़िया को बनाने के लिए उसने ब्रेकथ्रू टी1डी- एक टाइप 1 डायबिटीज अनुसंधान और वकालत संगठन के साथ साझेदारी की है, जिसे पहले जुवेनाइल डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन या जेडीआरएफ के नाम से जाना जाता था। यह संगठन टाइप 1 डायबिटीज पर रिसर्च करता है और इस बीमारी से जूझ रहे लोगों की मदद करता है। इस सहयोग का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि गुड़िया का डिजाइन असली जिंदगी से मेल खाए और उस समुदाय की सही तस्वीर दिखाए। कैलिफोर्निया स्थित कंपनी ने बताया कि गुड़िया में ऐसे सहायक उपकरण लगाए गए हैं, जो टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए जरूरी होते हैं। जैसे- बांह पर कंटीन्यूअस ग्लूकोज मॉनीटर (सीजीएम)- यह एक छोटा सा उपकरण है जो लगातार ब्लड शुगर लेवल को मापता है। इसके अलावा, कमर पर इंसुलिन पंप- ये शरीर को जरूरी मात्रा में इंसुलिन देता है। हाथ में एक मोबाइल फोन- इसमें एसा ऐप दिख रहा है जो डायबिटीज को मैनेज करने में मदद करता है। नीला पर्स- इसमें जरूरी और खाने-पीने की चीजें रखी जा सकती हैं। इस बार्बी का कपड़ा भी नीले रंग का है, जिस पर सफेद पोल्का डॉट्स बने हैं। नीला रंग डायबिटीज जागरूकता का प्रतीक है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने आय से अधिक संपत्ति रखने और रिश्वतखोरी से जुड़े एक मामले में धन शोधन निरोधक कानून के तहत मध्य प्रदेश के एक पूर्व ईपीएफओ अधिकारी और उनके परिवार की 50 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति अटैच की है। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अधिकारी श्यामलाल अखंड के खिलाफ मंगलवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया। ईडी ने दावा किया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में एक प्रवर्तन अधिकारी के रूप में, अखंड ने 2009 और 2019 के बीच जांच अवधि के दौरान अपनी ज्ञात वैध आय से अधिक अवैध रूप से संपत्ति जमा करने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया।

ग्रैन्यूल्स ने अमेरिका में रक्तचाप कम करने वाली दवा की 33 हजार बोतलें वापस मंगाई- दवा कंपनी ग्रैन्यूल्स इंडिया विनिर्माण संबंधी समस्याओं के कारण अमेरिका में रक्तचाप कम करने वाली एक जेनेरिक दवा की 33 हजार से अधिक बोतलें वापस मंगा रही है। अमेरिकी खाद्य एवं दवा प्रशासन (एफडीए) ने ने अपनी हालिया प्रवर्तन रिपोर्ट में कहा कि हैदराबाद स्थित दवा विनिर्माता कंपनी 100 और 500 गोलियों वाली मेटोप्रोलोल सक्सीनेट विस्तारित-रिलीज टैबलेट की 33,024 बोतलें वापस मंगा रही है। अमेरिका स्थित ग्रैन्यूल्स फार्मास्युटिकल्स इंक ने कहा कि वह विनिर्देशों में विफल रहने के कारण भारत में उत्पादित खेप को वापस मंगा रही है। यूएसएफडीए ने कहा कि यह उत्पाद छठे महीने में स्थिरता अध्ययन में मानदंडों को पूरा करने में विफल रहा। ग्रैन्यूल्स ने 24 जून को राष्ट्रव्यापी श्रेणी-दो वापसी अभियान की शुरुआत की थी। यूएसएफडीए के अनुसार श्रेणी-दो वापसी अभियान तब शुरू किया जाता है, जब उल्लंघनकारी उत्पाद के उपयोग या संपर्क से अस्थायी या चिकित्सकीय रूप से प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं।

कार्लाइल समेत दो पर चार लाख का जुर्माना- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने क्रेस्ट ग्लोबल सर्विसेज में हिस्सा लेने के लिए गलत तरीके से ग्रीन चैनल रूट का उपयोग करने के लिए कार्लाइल और बेक्रेस्ट पर 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला क्रेस्ट में 23.6 प्रतिशत हिस्सा लेने से जुड़ा हुआ है।

धोखाधड़ी से एटीएम से निकाली गई रकम, एसबीआई को देना पड़ा हर्जाना- एक व्यक्ति के एटीएम से धोखाधड़ी से रकम निकालने के मामले में 11 साल बाद भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई को हर्जाना देना पड़ा है। एसबीआई के इस ग्राहक के एटीएम से 4 जनवरी, 2014 को तीन बार में 22,000 रुपये की नकदी निकाली गई थी। ग्राहक का दिल्ली के एसबीआई में खाता था। फिर इंडियन ओवरसीज बैंक के एटीएम से पैसे निकाले। इसके बाद उन्हें 22,000 रुपये निकासी के तीन संदेश आए। उन्होंने एसबीआई व आरबीआई बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराई। सफलता नहीं मिलने पर दिल्ली उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। 25 अक्तूबर, 2017 को दिल्ली जिला उपभोक्ता आयोग ने एसबीआई को 4 जनवरी, 2014 से वसूली तक 10त्न सालाना ब्याज सहित 20,000 रुपये वापस करने का निर्देश दिया।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

लॉर्ड्स में जो रूट ने जड़ा शतक, राहुल द्रविड़ का ये रिकॉर्ड तोड़ा

मैनचेस्टर (एजेंसी)। लीड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। वहीं इस दौरान इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने आखिरकार अपने फेवरेट वेन्यू में ये इंतजार खत्म कर दिया। ऐतिहासिक लॉर्ड्स स्टेडियम में जो रूट ने टीम इंडिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में एक यादगार शतक जमा दिया। ये रूट के टेस्ट करियर का 37वां शतक है और इसके साथ ही वो महान भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रविड़ और ऑस्ट्रेलिया के स्टार स्टीव स्मिथ से आगे निकल गए।

लॉर्ड्स में 10 जुलाई से शुरू हुए तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन बैटिंग के लिए उतरे रूट 99 रन पर नाबाद लौटे थे। ऐसे में हर किसी की नजरें इस पर थीं कि क्या वो दूसरे दिन अपना शतक पूरा कर पाते हैं या नहीं। लेकिन रूट ने नर्वस नाइंटीज की बाधा को पार किया और ये मुकाम हासिल कर लिया। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान रूट ने दिन की पहली ही गेंद पर चौका जमाते हुए अपना शतक पूरा कर लिया। इसके साथ ही वो सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले बल्लेबाजों में 5वें नंबर पर पहुंच गए।

इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड के लिए जो रूट को पहले सेशन में ही क्रीज पर उतरना पड़ा था। सिर्फ 44 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद रूट ने ऑली पोप के साथ मिलकर पारी को संभाला और टीम को बेहतर स्थिति में पहुंचाया। फिर उन्हें कप्तान बेन स्टोक्स का साथ मिला और दोनों ने दिन का खेल खत्म होने तक कोई विकेट नहीं गिरने दिया। हालांकि, दूसरे दिन रूट का शतक होने के बाद वह अपना विकेट गंवा बैठे।

जो रूट के नाम सबसे ज्यादा रिकॉर्ड

रूट के नाम अब 37 शतक हो गए हैं। उन्होंने इस तरह पूर्व भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रविड़ और ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा स्टार स्टीव स्मिथ को पीछे छोड़ दिया है। दोनों के नाम 36-36 शतक हैं। इस तरह सचिन तेंदुलकर, जैक कैलिस, रिकी पोंटिंग और कुमार संगाकारा के बाद रूट सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए हैं।

ऋषभ पंत डॉक्टरों की निगरानी में, लॉर्ड्स में चोट के बाद जुरेल को मिली विकेटकीपिंग

लंदन (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कहा कि भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन दूसरे सत्र के खेल के दौरान अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में चोट लगने के बाद मैदान से बाहर चले गए जिसके बाद वह चिकित्सकीय टीम की निगरानी में हैं।

BCCI ने एक बयान में कहा कि पंत पर चिकित्सकीय टीम की निगरानी है और उनकी जगह ध्रुव जुरेल को विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीसीसीआई ने कहा, 'टीम इंडिया के उप-कप्तान ऋषभ पंत के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में चोट लगी है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और वे चिकित्सकीय टीम की निगरानी में हैं। ऋषभ की अनुपस्थिति में ध्रुव जुरेल विकेटकीपिंग कर रहे हैं।'

चोट लगने के बाद मैदान में दिए गए उपचार के बाद भी पंत को कोई फायदा नहीं हुआ और वह मैदान से बाहर चले गए जिनकी जगह ध्रुव जुरेल को भेजा गया जबकि वह तीसरे टेस्ट के लिए अंतिम एकादश में भी शामिल नहीं थे। पारी के 34वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की गेंद को लेग साइड में रोकने के लिए डाइव लगाने के बाद पंत दर्द से कराह रहे थे।

पंत गेंद पर हाथ लगाने में कामयाब रहे लेकिन इसे पूरी तरह से रोक नहीं पाए। इसके बाद खेल कुछ देर के लिए रुका रहा क्योंकि भारतीय सहयोगी स्टाफ पंत के हाथ का उपचार करने के लिए मैदान में थे। लेकिन खेल फिर से शुरू होने पर वह विकेटकीपिंग करने में असमर्थ हो गए। अंत में बुमराह का ओवर समाप्त होने के बाद पंत मैदान से बाहर चले गए और जुरेल ने विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाली।

अंपायर से भिड़ गए कप्तान शुभमन गिल, जमकर हुई बहस

लॉर्ड्स (एजेंसी)। लॉर्ड्स में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय कप्तान शुभमन गिल को गुस्से में देखा जा सकता है। पहले सेशन में गिल के साथ ही तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज अंपायर्स पर भड़कते दिख रहे हैं। इस दौरान की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं।

दरअसल, इंग्लैंड की पारी के 91वें ओवर में हुई, जब भारत दूसरे दिन के पहले घंटे के खेल के दौरान बेन स्टोक्स, शतकवीर जो रूट और क्रिस वोक्स को आउट करने के बाद मैच पर हावी था। 91वें ओवर की कुछ गेंदों के बाद जब दूसरी नई गेंद 10.4 ओवर पुरानी थी, गिल ने गेंद के आकार को लेकर शिकायत की। अंपायर पॉल रीफेल ने अपनी जेब से रिंग निकाली और गेंद टेस्ट में पास नहीं हुई। इससे गेंद में बदलाव का संकेत मिले, क्योंकि चौथे अंपायर बॉल बॉक्स लेकर आया। अंपायरों ने एक गेंद चुनी और गिल तुरंत उससे नाखुश हो गए।

उन्होंने अंपायर शरफुद्दौला से तीखी बहस की। गिल पीछे हटने को तैयार नहीं थे और लगातार शिकायत करते रहे, लेकिन उन्हें अपनी फील्डिंग पोजीशन पर वापस जाने को कहा गया ताकि खेल फिर से शुरू हो सके। सिराज अंपायर के पास गए और गेंद को देखा, उसके बाद स्टंप माइक पर उन्हें ये कहते सुना गया, ये 10 ओवर पुरानी गेंद हैं? सचमुच?

इंग्लैंड के खिलाफ पांचवे मैच में भी जीत के इरादे से उतरेगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम

लॉर्ड्स (एजेंसी)। लंदन (ईएमएमएस)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम शनिवार को यहां बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ जारी पांचवें और अंतिम मैच को भी जीतने के इरादे से उतरेगी। भारतीय टीम ने पहले ही ये सीरीज जीत ली है। ऐसे में उसका मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा। भारतीय टीम इस सीरीज में 3-1 से आगे हैं। इस मैच को जीतने के साथ ही उसकी बढ़त 4-1 हो जाएगी। भारतीय टीम ने पिछले सप्ताह एजबेस्टन में दूसरे टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया था जिससे वह इस मैच में भी जीत की प्रबल दावेदार है। उत्सुक होगी। भारतीय गेंदबाजों विशेषकर स्पिनरों अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं इंग्लैंड के बल्लेबाज भारतीय स्पिनरों के सामने संघर्ष करते दिखे हैं। इस सीरी में अब तक स्पिनरों ने 22 विकेट लिए हैं। राधा यादव और श्री चरणी ने इस सीरीज में जबरस्त प्रदर्शन किया है। वहीं दूसरी ओर केवल एक मैच जीती

मेजबान इंग्लैंड की महिला टीम के लिए स्पिनर दीप्ति शर्मा के नेतृत्व में भारत के स्पिन आक्रमण का सामना करना आसान नहीं रहेगा। बल्लेबाजी में भारत की स्मृति मंधाना ने अब तक सबसे अधिक रन बनाये हैं। उन्होंने शेफाली वर्मा के साथ मिलकर भारत को आक्रामक शुरुआत दिलाई है। जेमिमा रोड्रिग्स मध्यक्रम में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं हालांकि कप्तान कहरमनप्रीत कौर अभी तक अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं दिखीं हैं।।

वहीं इंग्लैंड के लिए कप्तान नैट साइवर-ब्रंट के बिन परेशानी बढ़ गयी है। ब्रंट फिट नहीं होने के कारण बाहर हो गयी हैं। इससे उसका संतुलन गड़बड़ा गया है। उसके बल्लेबाजों में सोफिया डंकले ही केवल रन बना रही हैं। सलामी बल्लेबाज़ डंकले और डैनी वायट-हॉज अच्छी शुरुआत नहीं दे पायी हैं। उसका मध्यक्रम भी लड़खड़ा गया है। गेंदबाजी विभाग में तेज गेंदबाज लॉरेन बेल ने छह विकेट लेकर अच्छा प्रदर्शन किया है पर उसने अन्य गेंदबाज फिसल हैं

दोनो ही टीमें इस प्रकार हैं

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, एन श्री चरणी, शुचि उपाध्याय, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, सयाली सतघरे।

इंग्लैंड: टैमी ब्यूमोंट (कप्तान), एम अर्लट, लॉरेन बेल, एलिस कैप्सी, चार्ली डीन, सोफिया डंकले, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन फाइलर, एमी जोन्स (विकेट कीपर), पैगी स्कोल्फील्ड, लिंसे स्मिथ, डैनी व्याट-हॉज, इसी वोंग, माइया बाउचियर।

आईसीसी नियम के अनुसार जुरेल नहीं कर सकेंगे ऋषभ की जगह पर बल्लेबाजी

लॉर्ड्स (। यहां इंग्लैंड के खिलाफ जारी तीसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले ही दिन भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की अंगुली में चोट लग गयी जिसके बाद उनकी जगह पर विकेकीपिंग करने के लिए ध्रुव जुरेल मैदान पर उतरे। ऋषभ के अब इस मैच मे विकेटकीपिंग करने की संभावना नहीं है। ऐसे में जुरेल ही विकेटकीपिंग संभालेंगे। जुरेल इस मैच में केवल विकेटकीपिंग ही करेंगे बल्लेबाजी नहीं कर पायेंगे। इसका कारण आईसीसी का एक नियम है। आईसीसी के इस नियम के अनुसार अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होता है तो उसका सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी ना तो गेंदबाजी कर सकता है और ना बल्लेबाजी या कप्तानी अंपायरों की सहमति से वह विकेट कीपिंज जरूर कर सकता है। नियमों में आगे कहा गया है, केवल एक नामित खिलाड़ी ही बल्लेबाजी कर सकता है और ऐसा तब भी कर सकता है, जब पहले एक सबस्टीट्यूट प्लेयर ने उसके लिए काम किया हो।

टॉस हारने में सबसे आगे है भारतीय टीम

लॉर्ड्स । भारतीय क्रिकेट टीम टॉस हारने के मामले में शीर्ष पर पहुंच गयी है। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में टॉस हारने के साथ ही भारतीय टीम के नाम ये अनचाहा रिकार्ड दर्ज हो गया है। भारतीय टीम अब तक लगातार 13 टॉस हारी है। वहीं वेस्ट इंडीज की टीम 12 बार टॉस हारी थी। इंग्लैंड के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में भारतीय कप्तान शुभमन गिल तीनों मैचों में टॉस हारे हैं। भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 2025 में आखिरी बार इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मैच के दौरान टॉस जीता था। भारत के नाम सबसे ज्यादा टॉस हारने का रिकॉर्ड है। भारत 31 जनवरी 2025 से 10 जुलाई 2025 तक कुल 13 मैचों में टॉस हारा है।

रोहित शर्मा से छिन सकती है वनडे टीम की कप्तानी, इस खिलाड़ी का नाम आ रहा सामने

नई दिल्ली (एजेंसी)। टेस्ट के बाद अब शुभमन गिल भारत की वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान बनने की जानकारी सामने आई है। फिलहाल इस पद पर रोहित शर्मा हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार गिल 2027 विश्व कप में भारत की कप्तानी करेंगे और निकट भविष्य में यह पद संभालेंगे। रोहित कब तक अपनी जगह बनाए रख पाएंगे, यह स्पष्ट नहीं है। अन्य रिपोर्टों का दावा है कि गिल अक्टूबर में भारत तीन मैचों की श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान वनडे टीम की कप्तानी करेंगे। दिसंबर 2024 में जब रोहित ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के पांचवें टेस्ट से खुद को अलग कर लिया था जो भारत के टेस्ट कप्तान के रूप में उनका आखिरी कार्यकाल भी था। इस बात की अटकलें तेज हो गई थी। उन्होंने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में टीम का नेतृत्व किया और भारत के लिए वनडे और टेस्ट खेलने की अपनी इच्छा बनाए रखी (उन्होंने 2024 टी20 विश्व कप जीतने के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले लिया)। हालांकि इंग्लैंड टेस्ट टीम की घोषणा होने से पहले ऐसी खबरें आईं कि बीसीसीआई चयनकर्ताओं ने रोहित को टेस्ट कप्तानी से हटाने का फैसला किया है। इसके तुरंत बाद, इस सीनियर स्टार ने इस प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी। रोहित वनडे विश्व कप जीतना चाहते हैं और उन्होंने इसका जिक्र भी किया था। ऐसे में जब विश्व कप 2027 में है तो रोहित फिट रहना चाहेंगे ताकि 2023 संस्करण के निराशाजनक प्रदर्शन को बदला जा सके, जहां भारत अहमदाबाद में फाइनल में हार गया था। वहीं उनके साथी विराट कोहली का भी यही लक्ष्य है जो टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं। गिल ने टेस्ट से पहले वनडे में खुद को स्थापित किया, और 2023 और 2024 में सलामी बल्लेबाज के तौर पर शानदार प्रदर्शन किया। इंग्लैंड में उनकी कप्तानी प्रभावशाली रही है, जिसमें अच्छे रणनीतिक फैसले और साथियों के साथ खुला संवाद शामिल है।

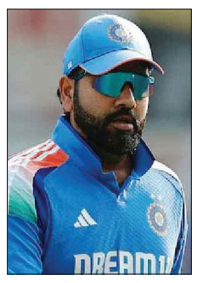

दो देशों के लिए खेल चुके पीटर मूर ने संन्यास की घोषणा की, 35 की उम्र में क्रिकेट को कहा अलविदा

नई दिल्ली (एजेंसी)। आयरलैंड के बल्लेबाज पीटर मूर ने 35 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। उन्होंने अपने करियर को अलविदा कहने से पहले 85 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। हरारे में जन्मे मूर ने आयरलैंड जाने से पहले जिम्बाब्वे के साथ अपना अंतरराष्ट्रीय करियर शुरू किया था। उन्होंने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच इसी साल फरवरी में बुलावायो में जिम्बाब्वे के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में खेला था।

नवंबर 2014 में, मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ एकदिवसीय मैच के दौरान मूर ने जिम्बाब्वे के लिए अपना अंतरराष्ट्रीय पदार्पण किया। उन्होंने 2016 में क्रमशः न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ अपना टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय पदार्पण किया। उनके 49 वनडे, 21 टी20 अंतरराष्ट्रीय और 8 टेस्ट मैच ज़िम्बाब्वे के लिए खेले। उन्होंने अक्टूबर 2022 में आयरलैंड के लिए खेलने के लिए अर्हता प्राप्त की, क्योंकि उनकी नानी की आयरिश विरासत के कारण उनके पास आयरिश पासपोर्ट था। उन्हें पहली बार मार्च-अप्रैल 2023 में बांग्लादेश और श्रीलंका के टेस्ट दौरों के लिए आयरलैंड की टीम में चुना गया था। इसके बाद उन्होंने आयरलैंड के लिए सात टेस्ट मैच खेले।

पीटर मूर ने कहा, 'मुझे अब भी लगता है कि शीर्ष स्तर पर मेरे अंदर तीन या चार साल का अच्छा क्रिकेट खेलने का मौका है। भले ही पिछले कुछ सालों में मैं जिम्बाब्वे के लिए कुछ विश्व कप से चूक गया हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं अगले विश्व कप में आयरलैंड के लिए खेल सकूंगा।' हालांकि मूर ने आयरलैंड के लिए कभी कोई वनडे या टी20 मैच नहीं खेला। वहां जाने के बाद उनका टेस्ट प्रदर्शन भी गिर गया, जिम्बाब्वे के लिए आठ टेस्ट मैचों में उनका औसत 35.53 रहा जिसमें 5 अर्धशतक शामिल थे, लेकिन आयरलैंड के लिए उनका औसत केवल 14.35 रहा जिसमें एक अर्धशतक शामिल था।

आयरलैंड के लिए उनका एकमात्र अर्धशतक जुलाई 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत में आया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 85 मैचों में इस बल्लेबाज ने 22.91 की औसत से 11 अर्धशतकों के साथ 1925 रन बनाए। मूर दो अलग-अलग देशों के लिए टेस्ट मैच खेलने वाले 17 क्रिकेटरों में से एक के रूप में संन्यास लिया।

भारत को नीतीश को टीम में बनाए रखना चाहिए : अनिल कुंबले

लंदन। पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले ने ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें टेस्ट टीम में नियमित रूप से शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने खुद को अनुशासन और प्रतिभा का बेहतरीन मिश्रण साबित किया है। इंग्लैंड के मौजूदा दौरे में अपना दूसरा मैच खेल रहे रेड्डी गुरुवार को तीसरे टेस्ट के पहले दिन दो विकेट लेकर सबसे सफल भारतीय गेंदबाज रहे। कुंबले ने जियोस्टार से कहा, 'मैं यह देखकर हैरान था कि नीतीश कुमार रेड्डी ने कितनी अच्छी गेंदबाजी की। उन्होंने लगातार सही क्षेत्रों में गेंद डाली। वह भाग्यशाली थे जो उन्हें लेग साइड में डाली गई शॉर्ट पिच गेंद पर विकेट मिला लेकिन इसके अलावा उन्होंने पूरे दिन अनुशासित गेंदबाजी की।' उन्होंने कहा, 'नीतीश ने आस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था तथा शतक लगाया था। इसके अलावा उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी भले ही उन्हें ज्यादा विकेट नहीं मिले थे। टीम के मुख्य तेज गेंदबाजों को राहत देने और साझेदारी तोड़ने के लिए उनके जैसे गेंदबाज की जरूरत होती है।' इस दिग्गज लेग स्पिनर ने आगे कहा, 'उन्होंने एक स्पेल में लगभग 14 ओवर फेंके जिससे उनकी फिटनेस और गेंदबाजी पर नियंत्रण का पता चलता है। वह युवा हैं। अच्छे बल्लेबाज हैं और शतक लगा चुके हैं। वह अच्छे क्षेत्र रक्षक ही हैं। भारत को उन्हें टीम में बनाए रखना चाहिए और बदलाव करने के प्रलोभन से बचना चाहिए।'

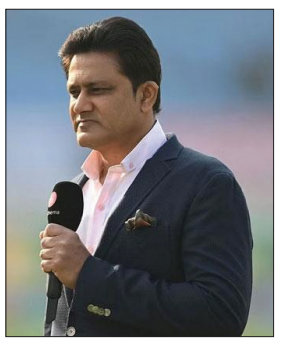

योगराज बोले गंभीर अच्छा काम कर रहे, सीरीज जीतेगी भारतीय टीम

चंडीगढ़ । पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह ने कहा है कि भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए उनकी आलोचना न करें। योगराज के अनुसार गंभीर के मार्गदर्शन और शुभमन की कप्तानी में भारतीय टीम इस सीरीज में जरुर जीतेगी। दोनो ही टीमें अभी सीरीज में 1-1 से बराबरी पर हैं। अपने विवादास्पद बयानों के लिए चर्चाओं में रहने वाले योगराज ने कहा, भारतीय खिलाड़ी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर अपना खेल सुधार रहे हैं। हमें हमेशा उनका समर्थन करना चाहिए। इसके अलावा गंभीर को लेकर भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी चाहिये क्योंकि वह अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, गंभीर, युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ अब क्रिकेट को अपनी तरफ से दे रहे हैं क्योंकि क्रिकेट से उन्हें बहुत कुछ मिला है। अब अगर हमारी टीम सीरीज हारती भी है तो भी हमें उनका समर्थन करन चाहिए। योगराज ने उम्मीद जताई है कि टीम इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में बेहतर करेगी। उन्होंने कहा, अगर आप हारते हैं तो आपको सफाई नहीं देना है; अगर आप जीतते हैं तब भी आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। हमें उम्मीद है कि हम शुभमन गिल की कप्तानी में सीरीज जीतेंगे। इससे पहले गंभीर का कोच के तौर पर रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। भारतीय टीम को उनके कोच रहते पहले न्यूजीलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी ही धरती पर हार का सामना करना पड़ा है। वहीं अब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की शुरुआत टीम रही है और टीम ने अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। युवा कप्तान शुभमन गिल ने जिस आत्मविश्वास से कप्तानी की है उससे उनके बढ़े हुए मनोबल का अंदाजा होता है।

विंबलडन 2025 : वर्बीक और सिनियाकोवा ने रचा इतिहास, जीता मिक्स्ड डबल्स खिताब

लंदन। चेक गणराज्य की कैटेरीना सिनियाकोवा और नीदरलैंड्स के सेम वर्बीक ने गुरुवार (स्थानीय समयानुसार) को विंबलडन 2025 का मिक्स्ड डबल्स खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में उन्होंने ब्रिटेन के जो सालिसबरी और ब्राज़ील की लुइसा स्टेफनी को सीधे सेटों में 7-6(3), 7-6(3) से हराया। सेंटर कोर्ट पर घरेलू खिलाड़ी सालिसबरी और उनकी जोड़ीदार स्टेफनी के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में चेक-डच जोड़ी ने संयम और आत्मविश्वास का परिचय दिया। दूसरे सेट में स्टेफनी को पैर में परेशानी भी नजर आई, जिसका असर उनकी मूवमेंट पर पड़ा। जीत का आखिरी बिंदु कैटेरीना सिनियाकोवा के ओवरहेड स्मैश के साथ आया, जिसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने खिताबी जीत का जश्न मनाया। यह दोनों की एक साथ पहली खिताबी जीत है। जहां सिनियाकोवा का यह पहला मिक्स्ड डबल्स ग्रैंड स्लैम खिताब है, वहीं 31 वर्षीय वर्बीक के करियर का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। खिताब जीतने के बाद 29 वर्षीय सिनियाकोवा ने कहा, 'यह बहुत खास है। इस टूर्नामेंट में खेलकर और जीतकर बहुत मज़ा आया। यह एक शानदार अनुभव था।'

टेनिस खिलाड़ी बेटी को पिता ने मारी गोलियां, अकादमी चलाने से नाराज था, लोग कसते थे तंज

गुरुग्राम (एजेंसी)। गुरुग्राम में एक पिता ने अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतका राधिका यादव एक टेनिस खिलाड़ी थी। पिता दीपक यादव ने अपनी बेटी पर 5 गोलियां चलाई जिनमें से तीन उसे लगीं। पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला गुरुग्राम के सुशांत लोक फेज 2 का है।

पुलिस ने बताया कि व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी बेटी की हत्या इसलिए की क्योंकि वह अपनी बेटी द्वारा टेनिस अकादमी चलाने से नाराज था और लोग उस पर फब्तियां कसते थे कि वह उसकी कमाई पर गुजारा कर रहा है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि पिता अपनी पुत्री के इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने से पसेशान था। पुलिस के मुताबिक उन्हें एक फोन आया था कि गोली लगने से घायल एक महिला को अस्पताल में मृत लाया गया है। पुलिस मृतक के घर गई और पाया कि वह एक टेनिस अकादमी चलाती थी और उसके पिता ने उसे गोली मार दी थी।

उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रारंभिक जांच के दौरान उसने अपनी बेटी की हत्या करना कबूल कर लिया। शिकायत आरोपी के भाई ने दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि दीपक अपनी बेटी द्वारा टेनिस अकादमी चलाने से नाराज था और उसे अकादमी बंद करने के लिए मजबूर कर रहा था। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान दीपक ने बताया कि उसकी बेटी ने कंधे में चोट लगने के बाद एक अकादमी खोली थी। जब भी वह वजीराबाद स्थित अपने गांव जाता था, तो लोग उसकी बेटी की कमाई पर गुजारा करने के लिए उस पर ताने कसते थे जिससे उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती थी।

दीपक ने बताया कि उसने अपनी बेटी से अकादमी बंद करने को कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया, जिससे वह नाराज हो गया। आज, उसने कथित तौर पर अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसे गोली मार दी। आरोपी के भाई ने अपनी शिकायत में कहा, %सुबह करीब 10 बजे, मुझे एक तेज आवाज सुनाई दी और जब मैं पहली मंजिल पर गया, तो मैंने अपनी भतीजी (राधिका) को रसोई में और बंदूक को ड्राइंग रूम में पड़ा देखा। मैं और मेरा बेटा उसे एशिया मारिंगो अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।' आरोपी के भाई ने कहा, 'मेरा भाई .32 बोर की रिवॉल्वर इस्तेमाल करता था, और वह उसी की थी।'

राधिका राष्ट्रीय स्तर की टेनिस खिलाड़ी थीं और उन्होंने कई प्रतियोगिताएं जीती थीं। 25 वर्षीय पीड़िता की गुरुग्राम सेक्टर-57 स्थित उसके घर में सुबह करीब 10 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने उसके पिता द्वारा इस्तेमाल की गई बंदूक जब्त कर ली है और मामले की जांच की जा रही है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

ब्रोकली की खेती

कर किसान कमाएं अधिक मुनाफा

ब्रोकली गोभीय वर्गीय सब्जियों के अंतर्गत एक प्रमुख सब्जी है। यह एक पौष्टिक इटालियन गोभी है। जिसे मूलतः सलाद, सूप, व सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्रोकली दो तरह की होती है - स्प्राउटिंग ब्रोकली एवं हेडिंग ब्रोकली। इसमें से स्प्राउटिंग ब्रोकली का प्रचलन अधिक है। हेडिंग ब्रोकली बिलकुल फूलगोभी की तरह होती है, इसका रंग हरा, पीला अथवा बैंगनी होता है। हरे रंग की किस्म ज्यादा लोकप्रिय है। इसमें विटामिन, खनिज लवन (कैल्शियम, फास्फोरस एवं लौह तत्व) प्रचुरता में पाये जाते हैं।

पौष्टिकता से भरपूर होने के कारण गर्भवती महिलाओं के लिए अधिक फायदेमंद है। देश के बड़े शहरों में इसकी अत्यधिक मांग होने के कारण इसकी खेती पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाने लगी है। उत्तराखंड में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। इसका बाजार भाव अधिक होने के कारण किसानों को अधिक आय प्रदान कर सकती है। अधिक मुनाफा देने के कारण किसान समाधान इसकी जानकारी लेकर आया है।

खेत की तैयारियां

ब्रोकोली के लिए दुमट अथवा बलुई - दुमट मिटटी वाली भूमि सर्वोतम मणि जाती है। अधिक अम्लीय भूमि इसके लिए अच्छी नहीं होती है। भूरी मिटटी एवं उपजाऊपन वाले खेत भी इसकी खेती हेतु उपयुक्त होते हैं, किन्तु उनमें जल निकास का उचित प्रबंध होना चाहिए। खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए अन्यथा पौधों की बढवार रुक जाती है और पौधे पीले पड़कर सड़ने लग जाते हैं। खेत की तैयारी के लिए दो जुताई पर्याप्त होती हैं, जिसमें अच्छी साड़ी गोबर की खाद दो कुन्तल प्रति नाली की दर से मिलाकर रोपाई हेतु भली - भाँति तैयार करना चाहिए।

बीज बुवाई का समय

अच्छे शीर्षों के निकलने एवं विकास के लिए 12 - 16 डिग्री सेन्टीग्रेट तापमान उपयुक्त होता है। अतः बीज की बुवाई एवं रोपाई के समय का निर्धारण उचित तापमान तथा क्षेत्र विशेषकर एवं वातावरणीय प्रस्थिति को ध्यान में रखते हुये किया जाना चाहिए।

निचले पर्वतीय क्षेत्र - सितम्बर अन्त से अक्तूबर
मध्य पर्वतीय क्षेत्र - मध्य अगत से सितम्बर
वेमौसमी खेती हेतु नवम्बर से मध्य जनवरी
ऊँचे पर्वतीय क्षेत्र - मार्च अथवा अप्रैल

बीज दर

ब्रोकोली के लिए 400 - 500 ग्राम बीज प्रति हैक्टेयर (8 - 10 ग्राम प्रति नाली) पर्याप्त होता है।

पौधशाला की तैयारी

जमीन से 15 सेमी. उठी हुयी नर्सरी की क्यारी में अच्छी साड़ी हुयी गोबर / कम्पोष्ट खाद तथा 50 - 60 ग्राम प्रति वर्गमीटर की दर से सिंगल सुपर फास्फेट मिलाकर भूमि की तैयारी करनी चाहिए। पौधशाला में भूमिगत कीटों एवं व्याधियों से बचाव के इए यह उपाय अपनायें।

क्यारी में 5 ग्राम थायरम प्रति वर्गमीटर की दर से अच्छी प्रकार मिलाकर 5 - 7 सेमी. की दुरी पर 1.5 - 2 सेमी. गहरी कतारें निकालें। तत्पश्चात कवकनाशी 10 ग्राम ड्राईकोडर्मा या एक ग्राम कार्बेन्डाजिम अथवा 2.5 ग्राम थाइरम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से शोधित बीज की बुवाई करें तथा जमने तक हल्की सिंचाई फव्वारे द्वारा करें। अधिक वर्ष से बचाव हेतु नर्सरी की क्यारी को घासफूस की छपर अथवा पालीथीन शीट से ढकने का प्रबन्ध रखना चाहिए। बेमौसमी खेती हेतु पौध पालीहाउस अथवा पालिटनल के अन्दर तैयार करनी चाहिए। पालीहॉउस अथवा पालीटनल के अन्दर भी पौधशाला में जड़ों में तापमान आवश्यकता से कम होने पर पालीहाउस में हीटर लगा दें। इससे बीजों का जमाव शीघ्र होने में मदद मिलेगी।

रोपाई

रोपाई हेतु 25 - 30 दिन की पौध उपयुक्त होती है। अतः पौध तैयार होने पर रोपाई शीघ्र करें। रोपाई से पूर्व नत्रजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा और 500 ग्राम थीमेट प्रति नाली की दर से खेत में छिड़क कर अच्छी तरह खेत तैयार कर लें। उसके बाद कतार से कतार की दूरी 45 - 50 सेमी. तथा पौध की दुरी 45 - 50 सेमी. रखते हुये पौध रोपाई कर हल्की सिंचाई करें। यदि कुछ पौधे मर गये हों अथवा बढवार अच्छी न हो तो उनके स्थान पर नई पौध की पुन : रोपाई एक हफ्ते के अन्दर कर दें। रोपाई के एक माह बाद शेष आधी नत्रजन मात्रा छिड़क कर पौधों के चारों तरफ मिटटी चढायें।

खाद या उर्वरक

उर्वरको का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करना उपयुक्त रहता है। अच्छी उपज के लिए प्रति हैक्टेयर 15 - 20 टन गोबर / कम्पोष्ट खद, 100 किलोग्राम नत्रजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस तथा 50 किलोग्राम पोटाश का प्रयोग किया जाना अनुकूल होता है।

खरपतवार नियंत्रण

शुरू के डेढ़ से दो माह तक खेत से खरपतवार निकलते रहें जिससे पौधों की बढवार अच्छी हो सके। इसके लिए आवश्यकतानुसार दो से तिन निराई - गुडाई पर्याप्त होगी।

जड़ विगलन

इस रोग के कारण रोपाई के उपरान्त कुछ पौधों की बढ़वार रुकी हुई दिखायी पड़ती है। पौधों को उखाड़कर देखने पर पत्ता चलता है कि इनकी जड़ें गलकर केवल एक तार की तरह हो गई हैं। इसकी रोकथाम के लिए बीज उपचार आर्द्रगलन रोग जैसा करें, रोपाई के समय पौध को दावा के घोल में डुबोकर लगायें तथा रोग के लक्षण खेत में दिखाई देने पर कार्बेन्डाजिम का 0.1 प्रतिशत की दर (एक ग्राम / लीटर पानी) से घोल बनाकर पौधों की जड़ों के पास छिड़काव करें तथा उचित फसलचक्र भी अपनायें।

कलि पर्णचिती रोग व मृदुल आसिता :-

इस रोग के कारण पत्तियों पर काले या भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। इसके नियंत्रण हेतु मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से पौधों में छिड़काव करें।

कीट नियंत्रण

माहू :- इस कीट के व्यस्क तथा शिशु दोनों ही मुलायम पत्तियों से रस चूसकर पौधों को हानि पहुंचाते हैं। पत्तियां पिली पद कर सूखने लगती हैं। प्रकोप अधिक होने पर गोभी के शीर्षों में भी माहू दिखायी पड़ते हैं। इसके नियंत्रण हेतु एजेडारेकटीन 1 - 2 मिली. अथवा इमिडाक्लोप्रिड 0.3 मिली. प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

गोभी की तितली

यह एक सफ़ेद रंग की तितली हैं, जिसके पीले रंग के अंडे गुच्छे में पत्तियों के पिछली स्थ पर बहुतायत में दिखाई पड़ते हैं। अंडो से निकलने वाली शुरुआती अवस्था से ही पत्तियों को भरी मात्रा में क्षति पहुंचती हैं। इसके नियंत्रण हेतु सबसे अंडों को चुनकर नष्ट कर दें फिर नियंत्रण हेतु इंडोसल्फान 35 ई.सी.का 2 मिली. अथवा इंडोक्साकार्ब 14.5 ई.सी. का 0.2 मिली. या बैसिलस थुरिंजीयेन्सिस का 1.5 - 2.0 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

फसल की कटाई

ब्रोकोली के शीर्ष की कटाई शीर्ष की कलियों के खुलने से पहले ही की जाती है। शीर्ष को 10 - 20 से.मी. तने (डंठल) के साथ काट लिया जाता है। इसके पश्चात् निचले पत्तों के कक्षों से नई कोपलें निकलती है जिनमे छोटे - छोटे शीर्ष बनते हैं। इन्हें भी समय - समय पर काट लेना चाहिए।

उपज

ब्रोकोली की औसत उपज 150 - 200 कुन्तल प्रति हैक्टेयर (3 - 4 कुन्तल प्रति नाली) है।

अनुमोदित किस्में

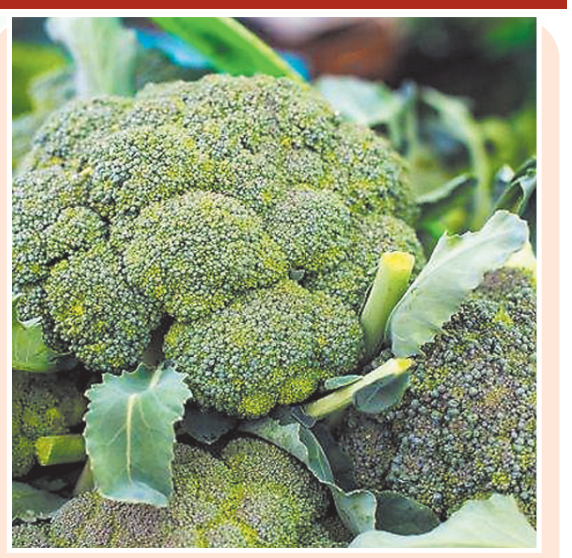

के.टी.एस.- 1 :-

इस किस्म के शीर्ष हरे रंग के कोमल डंठल युक्त होते हैं, जिनका औसत वजन 200 - 300 ग्राम होता है और रोपाई के लगभग 80 - 90 दिनों बाद काटने योग्य हो जाता है। मुख्य शीर्ष काटने के कुछ दिनों बाद छोटे - छोटे शीर्ष शाखाओं की तरह मुख्य भाग के रूप में पत्तियों के कक्षों से निकलते हैं उन्हें भी काटकर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है।

पालक समृद्धि

यह किस्म भी हरे शीर्ष वाली स्प्राउटिंग ब्रोकोली किस्म है। जिसका शीर्ष भाग बड़ा एवं लम्बे कोमल डंठल युक्त होता है। प्रत्येक शीर्ष का औसत वजन 25- - 300 ग्राम होता है। मुख्य शीर्ष को काटने के बाद छोटे - छोटे शीर्ष पत्तों के कक्षों से निकलते हैं। यह किस्म 85 - 90 दिनों में रोपाई के बाद कटाई योग्य हो जाती है। इसमें येलो आई रोग एवं ब्रैक्टिंग विकार के लिए प्रतिरोधिता पायी जाती है।

एन.एस.- 50

यह मध्यम अवधि में तैयार होने वाली संकर किस्म है। इनके हेड गठीले, समरूप एवं गुम्बदाकार होते हैं। यह किस्म कैट आई से रहित है। इसके पौधे मृदुरोमिल आसिता एवं काला सडन रोग के प्रति सहनशील है। इसका बीज नामधारी मार्क से बाजार में मिलता है।

ब्रोकोली संकर - 1 :

इसकी परिपक्वता रोपाई के 60 - 65 दिन बाद होती है। इसके शीर्ष हरे रंग के गठीले होते हैं, जिसका औसत वजन 600 - 800 ग्राम होता है। इसके बीज राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा किसानों को उपलब्ध कराये जाते हैं।

टी.डी.सी. - 6 :

इसके शीर्ष हरे रंग के होते हैं, जिसका औसत वजन 600 - 800 ग्राम होता है। इसकी फसल रोपाई के 65 - 70 दिन बाद तैयार हो जाती है। इसकी बुवाई दर 300 - 350 ग्राम प्रति हैक्टेयर अनुमोदित की गयी है। इस प्रजाति के बीज उत्तराखंड तराई बीज निगम, पंतनगर द्वारा किसानों को उपलब्ध कराये जाते है।

रोग नियंत्रण

इस फसल में बीमारियों का प्रकोप अधिक नहीं होता है किन्तु रोपाई के बाद कुछ कीटों एवं व्याधियों का प्रकोप हो सकता है।

आर्द्रपतन

पौध जमीन की स्थ से गलकर मरने लगती है। इसके उपचार एवं रोकथाम के लिए निम्न उपाय अपनाने चाहिए।

भूमि में जल निकास का उचित प्रबन्ध करें।
नर्सरी का स्थान ऊँची जगह पर चुने एवं हर वर्ष बदलते रहें।
कार्बेन्डाजिम एक ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार कर बुवाई करें अथवा जैविक विधि से बीज उपचार हेतु ट्राइकोडर्मा विरिडी (4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज) अथवा ट्राइकोडर्मा हरजियानम 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज अथवा 25 ग्राम ट्राइकोडर्मा एवं 2.5 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर प्रति नाली की दर से पौधशाला की मिटटी में मिलायें।
नर्सरी में बीज की घनी बुवाई न करें और बुवाई कतारों में करें।
पौधशाला को सौर्यकरण द्वारा निर्जिविकरण करें।
बुवाई के 10 दिन बाद कार्बेन्डाजिम की 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर क्यारियों को तर करें तथा पुः 15 - 20 दिन बाद इसी दावा के घोल से क्यारी को ट्र कर लें।

चीकू की आधुनिक खेती कैसे करें ?

चीकू की खेती भारत के आंध्रप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में की जाती है। हाल के वर्षों में इसकी खेती अलग - अलग राज्यों में होने लगी है। इसकी खेती में कम लगत में अधिक मुनाफे के कारण तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इस फल के लिए एक खास बात यह है की इसकी खेती के लिए कम सिंचाई के साथ - साथ रख - रखाव आसान है। सबसे बड़ी बात है की इसकी अधिक मांग रहने से बाजार आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन उन्नत तरह से खेती करने से चीकू का उत्पादन अधिक होता है।

उन्नत किस्में

बड़े फल तथा पतले छिलके के साथ गुदा मीठा अच्छे चीकू का पहचान है इसलिए इसकी उन्नत किस्मों का अधिक ध्यान रखना जरुरी है। चीकू की उन्नत किस्में क्रिकेट बाल, कलि पत्ती, भूरी पत्ती, पी.के.एम.1, डीएसएच - 2 झुमकिया, आदि किस्में अति उपयुक्त है। क्रिकेट की बाल, कालीपट्टी, कलकत्ता राउंड, कीर्तिभारती, द्वारापुड़ी, पाला, पीकेएम -1, जोनावालासा ढ्ढ और ढ्ढढ्ढ, बैंगलोर, वावी वलसा आदि परन्तु उत्तरभारत में बारहमासी किस्म ज्यादा फेमस है।

पौध प्रवर्धन

चीकू की पौध बीज तथा कलम, भेट कलम से तैयार की जाती है लेकिन व्यवसायिक खेती के लिए किसान को शीर्ष कलम, तथा भेंट कलम विधि द्वारा तैयार पौधों को ही बोना चाहिए। पौध तैयार करने की सबसे उपयुक्त समय मार्च - अप्रैल है।

पौधों की रोपाई

पौधों की रोपाई वर्ष ऋतू में उपयुक्त रहती है। पौधों की रोपाई से पहले पौधों के लिए जड़ों को तैयार जरुर कर लेना चाहिए। इसके लिए गर्मी के दिनों में ही 7 - 8 मी. दुरी वर्गाकार विधि से 90 से.मी. गहरा आकार के गड्ढे तैयार कर लेना चाहिए। गड्ढों को भरते समय मिट्टी के साथ लगभग 30 किलोग्राम गोबर की अच्छी तरह सड़ी खाद, 2 किलोग्राम करंज की खली एवं 5 - 7 कि.ग्रा. हड्डी का चुरा प्रत्येक गद्दे में डालकर भर देना चाहिए। पौधों को बोने के बाद जड़ों में मिट्टी भरकर थाला बना लें।

खाद एवं उर्वरक का उपयोग

पेड़ों में समय - समय पर खाद देते रहना चाहिए, जिससे पौधों का विकास 10 वर्षों तक होता रहे। पोधों के रोपाई के एक वर्ष बाद 4 - 5 टोकरी गोबर की खाद, 2 - 3 कि.ग्रा. अरण्डी / करंज की खली एवं 50:25:25 ग्रा. एन.पी.के. प्रति वर्ष डालते रहना चाहिए। यह मात्रा 10 वर्ष तक बढ़ाते रहना चाहिए तत्पश्चात 500:250:250 ग्रा. एन.पी.के. की मात्रा प्रत्येक वर्ष देना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए की खाद और उर्वरक का उपयोग केवल जून तथा जुलाई में ही करना चाहिए। खाद सीधे जड़ में नहीं डालें बल्कि इसके लिए पौधे से दूर एक नाली बना लें उस नाली से खाद का घोल बनाकर दें।

सिंचाई

बरसात के मौसम में सिंचाई की जरुरत नहीं पड़ती है लेकिन गर्मी के मौसम में 7 दिन पर तथा सर्दी के मौसम में 15 दिन पर सिंचाई करने से पौधों में फल तथा फूल अच्छे लगते है।

पौधों की देख रेख तथा काट छांट

चीकू के पौधों को विशेष रूप से सर्दी के मौसम में पाले से बचाना जरुरी रहता है। यह खास ध्यान पौधों की रोपाई के 3 वर्ष तक रखने की जरुरत है। इसके लिए छोटे पौधों को बचाने के लिए पुआल या घास के छप्पर से इस प्रकार ढक दिया जाता है कि वे तीन तरफ से ढके रहते हैं और दक्षिण - पूर्व दिशा धूप एवं प्रकाश के लिए खुली रहती है। पौधों की रोपाई के समय मूल वृत्त पर निकली हुई टहनियों को काटकर साफ कर देना चाहिए। पेड़ का क्षत्रक भूमि से 1 मी. ऊँचाई पर बनने देना चाहिए। जब पेड़ बड़ा हो जाता है, तब उसकी निचली शाखायें झुकती चली जाती है और अन्त में भूमि को चुने लगती है तथा पेड़ की ऊपर की शाखाओं से ढक जाती है। इस शाखाओं में फल लगने भी बंद हो जाते हैं। इस अवस्था में इन शाखाओं को छीलकर निकाल देना चाहिए।

पुष्पन एवं फलन

शीर्ष कलम तथा भेंट कलम के द्वारा तैयार पौधों में 2 वर्षों के बाद फूल एवं फल आना आरम्भ हो जाता है। इसमें फल साल में 2 बार आते है। पहली फ़रवरी से जून तक और दूसरा सितम्बर से ऑक्टोबर तक। फूल लगने से लेकर फल पककर तैयार होने में लगभग चार महीने लग जाते हैं। चीकू के पौधों से फल को गिरने से रोकने के लिए फूल के समय जिबरेलि अम्ल के 50 से 100 पी.पी.एम. अथवा फल लगने के तु बाद प्लैनोफिक्स 4 मिली./ली. पानी के घोल का छिड़का करने से फलन में वृद्धि एवं फल गिरने में कमी आती है।

रोग एवं कीट नियंत्रण

चीकू की पौधों में एक विशेषता यह रहती है की इस पर रो तथा कीटों का प्रकोप कम होता है। इसके बाबजूद भी पर्ण द रोग तथा कलि बेधक, तना बेधक, पत्ती लपेटक एवं मिलीब आदि कीटों का प्रभाव देखा जाता है। इसके नियंत्रण के लि मैंकोजेब 2 ग्रा./ लीटर तथा मोनोक्रोटोफास 1.5 मिली लीटर के घोल का छिड़काव करना चाहिए।

उपज

चीकू में रोपाई के दो वर्ष फल मिलना प्रारम्भ हो जाता। जैसे - जैसे पौधा पुराना होता जाता है। उपज में वृद्धि हो जाती है। एक 30 वर्ष पेड़ से 25,00 से 3,000 तक फल प्रति वर्ष हो जाते हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पटरी से उतरी मालगाड़ी, मुंबई-पुणे रेल यातायात हुआ बाधित

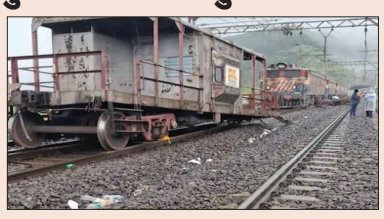

मुंबई (एजेंसी)। मुंबई-पुणे रेलमार्ग के खंडाला घाट पर मंकी हिल के पास एक मालगाड़ी के डिब्बे के पहिए उतर जाने से मुंबई से पुणे जाने वाला रेल यातायात बाधित हो गया है। खबर है कि पुणे जाने वाली एक मालगाड़ी के सुरक्षा गार्ड के डिब्बे के पहिए उतर जाने से घाट पर पुणे की ओर जाने वाला यातायात रोक दिया गया है। इसके कारण चेन्नई एक्सप्रेस, जोधपुर-हडपसर एक्सप्रेस, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस ट्रेनें देरी से चल रही हैं। जबकि अन्य ट्रेनों को दूसरे रूट पर डायवर्ट किए जाने की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा, कर्जत और पलसधरी मार्गों पर मुंबई से पुणे जाने वाली मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर ट्रेनें और मालगाड़ियां रोक दी गई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कर्जत और लोनावला के बीच एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। इसके कारण मुंबई से पुणे जाने वाला यातायात बाधित हो गया है। रेल प्रशासन ने जानकारी दी है कि यातायात को सामान्य करने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। पटरी से उतरे ट्रेन के डिब्बे को जल्द ही पटरी पर लाया जाएगा और यातायात बहाल किया जाएगा। ज्ञात हो कि मुंबई-पुणे रेल मार्ग पर प्रतिदिन लाखों यात्री यात्रा करते हैं। कई लोग नियमित रूप से मुंबई से पुणे आते-जाते हैं। कई लोग काम के सिलसिले में प्रतिदिन इस मार्ग से यात्रा करते हैं। इसलिए, मुंबई-पुणे रेलमार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों को इससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में दो बांग्लादेशी गिरफ्तार

इंफाल (एजेंसी)। बांग्लादेश के दो नागरिकों को बिना वैध दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करने के आरोप में मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले से गिरफ्तार किया गया है। सीमा सुरक्षा बल और मेघालय पुलिस की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। शिलांग के पास मावलाई बाईपास पर गुवाहाटी जा रही एक कार को रोका गया, जिसमें सवार सभी से पूछताछ की गई। पूछताछ में दो बांग्लादेशी नागरिक वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ पाए गए। इसके अलावा सीमा पार में उनकी मदद करने वाले दो और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। चारों की गुवाहाटी जाने की योजना थी। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए लगातार निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी। गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस घटना से सीमा सुरक्षा में सतर्कता बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया गया है।

खूंटी में धंस गया पुल, अब जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे बच्चे

खूंटी (एजेंसी)। बारिश के कारण देश के कई राज्यों से पुल टूटने और कई सड़कें धंसने की खबर सामने आई। कुछ ऐसा ही हादसा हाल ही में झारखंड के रांची के पास खूंटी-सिमडेगा मार्ग पर पेलौल गांव के पास बनई नदी पर बना पुल तेज बारिश में धंस गया था। पुल का एक पिलर झुकने से स्लैब करीब 20 फीट नीचे चला गया है, जिसके चलते लोगों को बांस की सीढ़ी लगानी पड़ी थी। लोग अब इस बांस की सीढी के सहारे चढ़कर पुल पार कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल जाने के लिए जान जोखिम उठाना पड़ रहा हैं, क्योंकि स्कूल जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब इसका वीडियो वायरल हो गया है। बता दें पिछले दिनों बनई नदी पर बना ये पुल तेज बारिश के कारण धंस गया था। इस ब्रिज के टूटने से बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया। स्कूल प्रबंधन ने बसें बंद कर दी, जिसके कारण बच्चों को टूटे पुल से जाना पड़ता है। बताया जा रहा है कि बारिश के बावजूद भी बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बच्चों के माता-पिता अपने निजी वाहन से बच्चों को धंसे पुल तक लाते हैं और यहां से बच्चों को 20 फीट की बांस की सीढी के सहारे नीचे उतारा जाता है। ऐसा रोज होता है। बारिश के कारण सीढ़ी बहुत फिसलन भरी और खतरनाक हो चुकी है। कई बार माता-पिता बच्चों को अपनी पीठ पर लादकर सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं और नीचे उतरते हैं। बांस की सीढ़ी के सहारे पुल पार करना आसान नहीं है। इसमें जान जाने का खतरा है।

स्टंटबाजी करते समय कार 300 फीट खाई में गिरी, बच गई युवक की जान

मुंबई (एजेंसी)। स्टंटबाजी के मामले आए दिन सुनने और देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसा ही स्टंटबाजी का मामला महाराष्ट्र के गुजरवाडी इलाके में स्थित प्रसिद्ध पर्यटक स्थल टेबल पॉइंट का है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। जहां एक युवक कार से स्टंट करते नजर आ रहा है और स्टंट के दौरान युवक की कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और कार करीब 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे की सूचना मिलते ही आस-पास के लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और गहरी खाई में गिरी कार से युवक को निकलने की कोशिश करने लगी। काफी देर की मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि टेबल पॉइंट पर कोई सुरक्षा रेलिंग या सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, जिसके चलते आए दिन इस तरह के हादसे होते हैं। पहले भी इस क्षेत्र में कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। बता दें टेबल पॉइंट सतारा जिले का एक लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। यह जगह खासकर के युवाओं और टूरिस्ट के बीच लोकप्रिय है, जो ज्यादातर यहां पर रील्स बनाने आते हैं, लेकिन इस जगह पर सुरक्षा सुविधाओं की कमी है, जिसके चलते आए दिन घटनाएं होती हैं।

मॉनसून सत्र छोड़कर दिल्ली पहुंचे शिंदे, अमित शाह से की मुलाकात

-कांग्रेस ने कहा- कैबिनेट में गैंगवार से बचने दिल्ली दरबार में गए गुहार लगाने

नई दिल्ली (एजेंसी)। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है और इस बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे उसे छोड़कर दिल्ली पहुंच गए। वह बुधवार को दिल्ली आए और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके अलावा उनकी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की खबरें सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चर्चा यह है कि आखिर एकनाथ शिंदे दिल्ली जाकर बड़े नेताओं से क्यों मिले हैं। कांग्रेस ने इसे महायुति में टकराव से जोड़ा है और उसका कहना है कि कैबिनेट में गैंगवार चल रहा है। इससे बचने के लिए ही वह दिल्ली दरबार में गुहार लगाने पहुंचे।

कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने कहा कि एकनाथ शिंदे राज्य कैबिनेट में चल रही गैंगवार से बचने दिल्ली गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक भी इस यात्रा को अहम मान रहे हैं क्योंकि उद्धव सेना और राज ठाकरे की मनसे के बीच एकता स्थापित हो रही है और दोनों ने मराठी भाषा के स्वाभिमान के नाम पर साझा रैली की है। ऐसी स्थिति में मराठा के नाम पर राजनीति करने वाली एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। माना जा रहा है कि इस पर मंत्रणा के लिए एकनाथ शिंदे दिल्ली आए थे।

चर्चाएं हो रही हैं कि राज्य में होने वाले आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में ठाकरे बंधु एक साथ आ सकते हैं। इससे चुनावी मूड में बीजेपी भी सतर्क है। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने एक आंतरिक सर्वेक्षण कराया है कि अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आते हैं तो महाराष्ट्र में एनडीए को कितना नुकसान होगा। समझा जाता है कि अमित शाह और शिंदे के बीच इस मामले पर बात हुई है। इसके अलावा शिंदे ने सरकार को लेकर भी अपनी कुछ चिंताएं जताई हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी की तरफ से भी कुछ कहा नहीं गया है।

यह भी चर्चा है कि यदि ठाकरे बंधुओं को चैलेंज दिया गया तो मराठी वोटर्स का रिएक्शन क्या होगा। शिंदे की पार्टी भी इसे लेकर चिंतित है। यही वजह है कि मनसे की ओर से आयोजित विरोध प्रदर्शन में एकनाथ शिंदे सेना के नेता प्रताप सरनाइक पहुंचे थे। यही नहीं उन्होंने मनसे के लोगों की गिरफ्तारी पर भी ऐतराज जताया था।

पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता की हत्या, पहले गोली मारी फिर धारदार हथियार से किया हमला

कोलकाता। पश्चिम बंगाल से आए दिन हिंसा और आगजनी की खबरें आ रहीं हैं। गुरुवार देर रात यहां एक टीएमसी नेता की बेहरमी से हत्या कर दी गई। दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर में तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता रज्जाक खान की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने रज्जाक खान पर पहले गोली चलाई और फिर धारदार हथियार से हमला कर उनकी जान ले ली। इस घटना ने इलाके में तनाव और दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि खान पर हमला उस समय हुआ जब वह सिरिस्ताला के पास अपने घर लौट रहे थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। मामले की औपचारिक जांच शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, खान पर भांगर बाजार से मारीचा लौटते समय एक नहर के पास घात लगाकर हमला किया गया। हमलावरों ने पहले उन पर गोली चलाई और फिर धारदार हथियारों से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। काशीपुर पुलिस स्टेशन को घटना की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। कोलकाता पुलिस के बयान के अनुसार, कल रात करीब 9:45 बजे, चक मारीचा गांव, चाल्टाबेरिया ग्राम पंचायत के निवासी राज्जाक खान पर उत्तर काशीपुर थाना क्षेत्र के सिरिस्ताला के पास कुछ लोगों ने हमला किया, जब वह घर लौट रहे थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। जांच शुरू कर दी गई है। कैनिंग पूर्व के विधायक सौकत मोल्ला ने दावा किया कि इस हमले के पीछे आईएसएफ समर्थित असामाजिक तत्वों का हाथ है और उन्होंने तत्काल उनकी गिरफ्तारी की मांग की।

महाराष्ट्र में एनडीए सरकार के होते हिंदुओं का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता

-मंत्री नितेश राणे ने राज ठाकरे को भी दिया चैलेंज

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने कहा है कि महाराष्ट्र में एनडीए सरकार होते हुए हिंदुओं को कोई नहीं डरा सकता। हम हिंदुओं के चौकीदार हैं। हम भी यहां खड़े हुए हैं। राणे ने शुक्रवार को मुंबई के बोरीवली में एक परियोजना का भूमिपूजन करने के बाद कहा की हमारी सरकार रहेगी, तभी देवताओं की रक्षा होगी। मुंबई का डीएनए हिंदू है और अब नगर निगम में सिर्फ भगवा झंडा ही रहेगा।

उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं के वोट से विधायक बना हूं। अगर मैं हिंदुओं की बात नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? मालवणी जाकर देखो, पहले वो कुछ दे भाऊ कहेंगे, फिर वही लोग तुम्हें बाप बनाने की कोशिश करेंगे। ये सांप हैं। बाद में मीडिया से बात करते हुए नितेश राणे ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे चैलेंज किया। मीरा रोड में राज ठाकरे की सभा पर राणे ने कहा कि सभी मदरसों से उर्दू हटाकर वहां मराठी अनिवार्य करो, तभी हमें यकीन होगा कि आपको महाराष्ट्र और मराठी से सच्चा प्यार है। सिर्फ दिखावटी मराठी बोलकर ढोंग करने की कोशिश मत करो, सबको सब समझ में आता है। राणे ने यह भी कहा कि जो मुस्लिम भाई राज ठाकरे की सभा में आए, अगर वाकई मराठी से प्रेम है तो अजान मराठी में शुरू करें। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर नितेश राणे ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राउत और ठाकरे एक होकर लड़ने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन जनता मातोश्री की नहीं और कलानगर की नहीं, हमारे साथ है। महाराष्ट्र की जनता ने हमें 10 महीने पहले वोट दिया है। हमें पाकिस्तान की जनता ने नहीं चुना।

बेंगलुरु नगर पालिका रोज आवारा कुत्तों को तीन लाख का खिलाएगी चिकन-चावल

-बीबीएमपी का उद्देश्य कुत्तों के आक्रामक व्यवहार पर काबू पाना

बेंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक सरकार टैक्सपेयर्स के पैसों से कुत्तों को चिकन चावल खिलाने की तैयारी कर रही है। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) ने करीब 2.9 करोड़ रुपए की अभूतपूर्व पहल शुरू करने जा रही है। इसमें आवारा कुत्तों के लिए रोज भोजन योजना शुरू की जाएगी। बीबीएमपी का उद्देश्य कुत्तों के आक्रामक व्यवहार पर काबू पाना और जन सुरक्षा को मजबूत करना है। इस पहल की शुरुआत बेंगलुरु शहर के आठ क्षेत्रों में 5,000 आवारा कुत्तों को खिलाने से शुरू होगी। नगर निगम ने बताया कि प्रतिदिन 367 ग्राम का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नगर निगम ने बताया कि कुत्तों को कैलोरी संतुलित खाना खिलाया जाएगा, जो एक सामान्य 15 किलोग्राम के कुत्ते की पोषण संबंधी जरुरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया है। 22.42 रुपए की थाली में 150 ग्राम चिकन, 100 ग्राम चावल, 100 ग्राम सब्जियां, 10 ग्राम तेल है। इससे 465-750 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। नगर निगम ने बताया कि बेंगलुरु में करीब 2.8 लाख आवारा कुत्ते हैं। बीबीएमपी प्रत्येक क्षेत्र में 400 से 500 कुत्तों को खिलाने के लिए वेंडर्स को शामिल करेगा, जो हरेक क्षेत्र में 100 से 125 जगहों पर खाना उपलब्ध करेंगे।

रिपोर्ट में बीबीएमपी के एक अधिकारी ने कहा कि यह पहली बार है जब भारत में किसी नगर निकाय ने आवारा पशुओं को सामूहिक भोजन देने की योजना बनाई गई है। यह सिर्फ एक कल्याणकारी कदम नहीं है- यह एक सुरक्षा पहल है। सरकार की इस कदम पर लोगों ने अपनी-अपनी राय दी। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ने इस योजना की तारीफ की है। वहीं, आलोचकों ने कुत्तों की नसबंदी करके उनकी आबादी पर लगाम लगाने के बजाय, उनके खाने-पीने के लिए करोड़ों रुपए के सरकारी धन के आवंटन की समझदारी पर सवाल उठाए हैं।

बेंगलुरु के जयनगर की रहने वाली एक महिला ने बताया कि पिछले हफ्ते ही मेरे बुजुर्ग पिता के पीछे आवारा कुत्ते पड़ गए थे वह किसी तरह बचकर घर आए। चिकन राइस पर करोड़ों रुपये खर्च करने के बजाय, बीबीएमपी को पहले कुत्तों की नसबंदी और उनकी आबादी नियंत्रित करने पर ध्यान देना चाहिए। खाना खिलाना कोई समाधान नहीं है। हुलीमावु के रहने वाले एक शख्स ने तर्क दिया कि यह एक स्वागत योग्य कदम है।

हममें से कई लोग पहले से ही अपने पैसों से आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं। बीबीएमपी मदद के लिए आगे आ रहा है, तो इससे बदलाव आएगा। बशर्ते यह काम जिम्मेदारी से और भ्रष्टाचार के बिना किया जाए।

पहले हरियाणा अब हिमाचल प्रदेश में भूकंप से हिली धरती

शिमला (एजेंसी)। हरियाणा के बाद अब हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश के बीच भूकम्प के झटके लगे हैं। पर्वतीय जिला चम्बा में शुक्रवार सुबह भूकम्प के हल्के झटकों से धरती हिली। भूकम्प की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.5 रही। ये झटके सुबह 6 बजकर 23 मिनट पर कुछ सेकंड तक रहे। इसका असर चम्बा जिला व आसपास के इलाकों में महसूस किया गया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश भूकम्प की दृष्टि से अति संवेदनशील जोन 4 व 5 में शामिल है। यहां कई वर्षों से भूकम्प के हल्के झटके महसूस किए जाते रहे हैं। वर्ष 1905 में कांगड़ा व चम्बा जिलों में आये विनाशकारी भूकंप से 10 हज़ार से अधिक लोग मारे गए थे।

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक भूकम्प का केंद्र चम्बा में 32.36 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 76.18 डिग्री पूर्वी देशांतर पर रहा और इसकी गहराई जमीन की सतह से पांच किलोमीटर नीचे दर्ज किया गया। भूकंप के झटकों के कारण किसी तरह का जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि भूकम्प की तीव्रता कम होने की वजह से चम्बा जिला व साथ लगते क्षेत्रों में किसी तरह के नुकसान की रिपोर्ट नहीं है। इससे पहले भी चम्बा जिला में कई बार कम तीव्रता के भूकम्प के झटके लग चुके हैं। हालांकि किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ था। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई सालों से भूकम्प के झटके लग रहे हैं। भूकंप का लगातार आना लोगों को दहशत में डाल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आगामी 16 जुलाई तक राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राजधानी शिमला सहित अन्य इलाकों में आज बादल छाए हैं, हालांकि बीती रात बारिश हुई।

केरल में खड़ा ब्रिटिश एफ-35 विमान, अगले हफ्ते भरेगा उड़ान!

-ब्रिटिश इंजीनियरों की टीम हाइड्रोलिक खराबी को ठीक करने में जुटी

नई दिल्ली(एजेंसी)। पिछले 27 दिनों से केरल के तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर फंसा ब्रिटेन का एफ-35बी लड़ाकू विमान अगले हफ्ते वापस जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगले सप्ताह तक इसकी मरम्मत पूरी हो सकती है। एक भारतीय अधिकारी ने बताया कि ब्रिटिश इंजीनियरों की एक टीम हाइड्रोलिक खराबी को ठीक कर रही है। उम्मीद है कि कुछ दिनों में विमान उड़ान भर सकेगा।

बता दें केरल में फंसा ब्रिटेन का यह फाइटर जेट पांचवीं पीढ़ी का विमान है। इसकी कीमत 115 मिलियन यूएसडी से भी ज्यादा है। 14 जून से यह विमान केरल के एयरपोर्ट पर ही खड़ा है। खराब मौसम और कम ईंधन के कारण इसे रॉयल नेवी के विमानवाहक पोत एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स से हटा दिया गया था। यह फाइटर प्लेन अरब सागर के ऊपर एक अभ्यास कर रहा था, तभी उसे केरल में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी।

फाइट जेट के अचानक रुकने से कई तरह के मीम और मजाक बनने लगे थे। केरल के पर्यटन विभाग ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी थी। एक एआई-जनरेटेड पोस्ट में विमान नारियल के पेड़ों से घिरा हुआ दिखाया गया था। इस मीम में लिखा था कि केरल एक शानदार जगह है, मैं यहां से जाना नहीं चाहता। राज्य के पर्यटन विभाग के प्रमुख ने कहा था कि यह ब्रिटेन के लोगों को धन्यवाद कहने का एक तरीका था। दरअसल, केरल में सबसे ज्यादा ब्रिटिश पर्यटक ही आते हैं। एक और कार्टून में विमान को स्थानीय स्नैक्स खाते हुए दिखाया गया था।

शुरुआत में फाइटर जेट को एयरपोर्ट के बे 4 पर खड़ा किया गया था। सीआईएसएफ के जवान इसकी रखवाली कर रहे थे। कई हफ्तों तक बारिश में भीगने के बाद इसे 6 जुलाई को हैंगर में खड़ा किया गया। इस बीच ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स के विशेषज्ञ एयरबस ए400एम एटलस विमान से केरल पहुंचे।

उदयपुर फाइल्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज

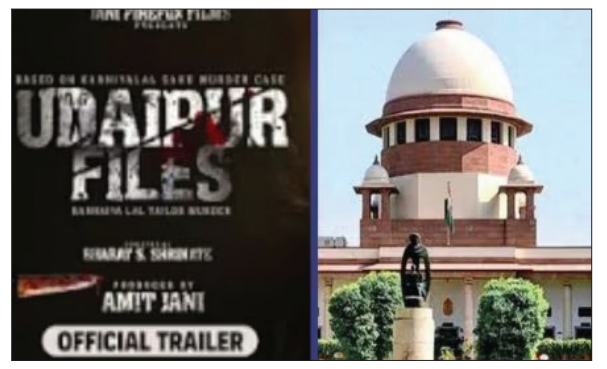

नई दिल्ली (एजेंसी)। उदयपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज कांवड़ यात्रा तक रोकने की मांग वाली याचिका को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद फिल्म की रिलीज से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई से इंकार कर याचिका को खारिज कर दिया।

दरअसल उदयपुर फाइल्स फिल्म शुक्रवार को ही रिलीज होनी थी। यह कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित है। 28 जून, 2022 को उदयपुर में मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने मिलकर दर्जी कन्हैयालाल का गला रेत दिया था। इस हत्याकांड के बाद पूरे देश में आक्रोश देखा गया था।

हालांकि इस फिल्म की रिलीज पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्थायी रूप से रोक लगाई। यह रोक तब तक लागू रहेगी जब तक केंद्र फिल्म को सेंसर बोर्ड से मिली मंजूरी के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर निर्णय नहीं ले लेती।

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ मामले में कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाओं में एक याचिका जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भी दायर की थी। उन्होंने फिल्म को मिले सीबीएफसी (केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड) प्रमाणन को रद्द करने की मांग की थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फिल्म पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह निर्माता को सुनवाई का मौका देकर एक सप्ताह के भीतर पुनर्विचार याचिकाओं पर निर्णय ले। यदि याचिका में अंतरिम राहत की मांग की गई हो, तब उस पर भी विचार कर निर्णय लिया जाए।

छांगुर बाबा को मुस्लिम देशों से हुई 500 करोड़ की फंडिंग... हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करने के लिए

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश की एंटी टेरर स्क्वॉड (एटीएस) ने शुक्रवार को सनसनीखेज खुलासा किया है। एटीएस ने बताया कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को बीते तीन सालों में करीब 500 करोड़ का विदेशी फंड प्राप्त हुआ। इसमें से 200 करोड़ की रकम आधिकारिक बैंकिंग माध्यमों से भारत पहुंची, जबकि 300 करोड़ अवैध हवाला चैनलों के माध्यम से नेपाल से भारत लाए गए। ये पैसे मुस्लिम देशों से आया। भारत में धर्मांतरण करवाने के इरादे से ये पैसे छांगुर बाबा को भेजा गया।

एटीएस की जांच में सामने आया है कि काठमांडू, नवलपरासी, रूपनदेही और बांके जैसे सीमावर्ती जिलों में 100 से अधिक बैंक खाते खुले, जिसमें पैसे जमा किए गए। ये फंड पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की जैसे मुस्लिम बहुल देशों से आए थे। इन खातों से पैसा नेपाल में स्थानीय एजेंटों के माध्यम से भारत पहुंचाया गया। एजेंट इसके एवज में 4-5 प्रतिशत कमीशन लेते थे। कई बार पैसे कैश डिपॉजिट मशीन के जरिए जमा किए गए।

नेपाल से भारत आने के बाद फंड को बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर जैसे जिलों में स्थानीय मनी एक्सचेंजर्स के माध्यम से भारतीय रुपये में बदल दिया जाता था। बिहार के मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, किशनगंज, चंपारण और सुपौल जिलों के एजेंट भी अवैध फंडिंग नेटवर्क में शामिल पाए गए हैं।

एटीएस के अनुसार, सबसे अधिक विदेशी फंडिंग अयोध्या जिले में पहुंची, जहां कथित तौर पर हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण हुआ। छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों से जुड़े 40 बैंक खातों की जांच शुरू हो चुकी है।

जांच के दौरान नवीन रोहरा के छह बैंक खातों में 34.22 करोड़ और नसरीन के खातों में 13.90 करोड़ मिलने की पुष्टि हुई है। एटीएस ने पिछले 10 वर्षों के आयकर रिकॉर्ड भी मांगे हैं। यह भी शक जताया जा रहा है कि छांगुर बाबा के दुबई, शारजाह या यूएई में भी बैंक खाते हो सकते हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

वहीं बलरामपुर स्थित छांगुर बाबा का 5 करोड़ की लागत से बना बंगला जमीनदोंज कर दिया गया है। यह बंगला सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना हुआ था। 40 कमरों वाले महलनुमा मकान में मार्बल का सुरक्षा गेट, विदेशी फर्नीचर, सीसीटीवी कमांड रूम और आधुनिक सुविधाएं थीं। बंगले को गिराने के लिए 10 बुलडोजर तैनात किए गए और तीन दिन की कार्रवाई में यह जमींदोज किया गया।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति येओल की गिरफ्तारी को मंजूरी

सियोल, एजेंसी। मार्शल लॉ का आदेश देने वाले दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सूक येओल को गिरफ्तार किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। एक अदालत ने विशेष अभियोजक की उस दलील को स्वीकार कर लिया कि येओल के कारण सबूतों को नष्ट किए जाने का खतरा है। इसी साल अप्रैल में देश के सांविधानिक न्यायालय ने महाभियोग को बरकरार रखने का फैसला सुनाया था। इसके बाद येओल को पद से हटा दिया गया। अब चार महीने बाद उन्हें सियोल के पास एक हिरासत केंद्र में रखा जाएगा। सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जनवरी में उनकी गिरफ्तारी को रद्द कर दिया था। मार्च में हुई रिहाई के समय अदालत ने उन्हें हिरासत में लिए बिना विद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी।

नासा के अंतरिम प्रशासक नियुक्त किए गए सीन डफी, राष्ट्रपति ट्रंप ने किए एलान

वॉशिंगटन, एजेंसी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परिवहन सचिव सीन डफी को नासा का अंतरिम प्रशासक नियुक्त किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह कदम राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में अंतरिक्ष के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने नई नियुक्ति की जानकारी सोशल मीडिया ट्रुथ के जरिए दी। सीन डफी को नासा का अंतरिम प्रशासक नियुक्त किए जाने की जानकारी देते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मैं हमारे परिवहन सचिव, सीन डफी को नासा का अंतरिम प्रशासक नियुक्त कर रहा हूं। सीन हमारे देश के परिवहन मामलों को संभालने में जबरदस्त काम कर रहे हैं, जिसमें अत्याधुनिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बनाना भी शामिल है। वह इस अत्यधिक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष एजेंसी के लिए एक शानदार नेता होंगे, भले ही केवल थोड़े समय के लिए ही क्यों न हों ? विस्कॉन्सिन से पूर्व सांसद और ट्रंप के लंबे समय से सहयोगी रहे डफी ने जेनेट पेट्रो का स्थान लिया है, जो जनवरी से कार्यवाहक नासा प्रशासक के रूप में कार्यरत थीं। ट्रंप ने मई में इस पद के लिए नामित जेरेड आइजैकमैन को दिसंबर 2024 नामित किया था, हालांकि बाद में उन्होंने उनका नाम वापस ले लिया।

अमेरिका में सीक्रेट सर्विस के 6 एजेंट सस्पेंड, डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ था जानलेवा हमला

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पिछले साल पेनसिल्वेनिया के बटलर में चुनावी रैली के दौरान जानलेवा हमला हुआ था। इस मामले में सीक्रेट सर्विस के छह एजेंटों को निलंबित कर दिया गया है। इन एजेंटों पर सुरक्षा में गंभीर चूक का आरोप है। सीक्रेट सर्विस के डिप्टी डायरेक्टर मैट क्विन ने सीबीएस न्यूज को बताया कि निलंबन की अवधि 10 से 42 दिनों के बीच है और इस दौरान उन्हें वेतन नहीं मिलेगा। हालांकि एजेंटों को बर्खास्त नहीं किया गया है, लेकिन निलंबन के बाद उनकी जिम्मेदारियां घटा दी जाएंगी और उन्हें कम संवेदनशील भूमिकाओं में तैनात किया जाएगा। क्विन ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, हम इसे बर्खास्तगी के जरिए हल नहीं करने जा रहे है। हम जड़ तक पहुंचकर उन खामियों को दूर करेंगे, जिनकी वजह से यह स्थिति पैदा हुई थी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव से पूर्व 2024 में पेंसिल्वेनिया में आयोजित एक चुनावी रैली में ट्रंप पर गोलियां चलाई गई थीं, जिसमें वे घायल हो गए थे। इस घटना ने अमेरिका की राजनीतिक सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया था कि हमलावर काफी देर तक आसपास मौजूद था, लेकिन सीक्रेट सर्विस उसे समय रहते पहचान नहीं सकी। हमले के बाद से सीक्रेट सर्विस की भूमिका और सुरक्षा तंत्र की समीक्षा हो रही थी। कई सांसदों और विशेषज्ञों ने सुरक्षा में अभूतपूर्व चूक करार देते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की थी।

लॉस एंजिलिस में निर्माणाधीन सुरंग ढही ; 15 श्रमिकों के फंसे होने की आशंका

लॉस एंजिलिस, एजेंसी। फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि बुधवार को लॉस एंजेलिस में निर्माणाधीन एक औद्योगिक सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था। जिसमें कुछ श्रमिक फंस गए थे। घटना के बाद चलाए गए राहत-बचावकार्य में 31 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। यह हादसा सुरंग के एकमात्र प्रवेश द्वार से 8 से 9.7 किलोमीटर अंदर हुआ। स्थानीय टेलीविजन की हवाई फुटेज में श्रमिकों को सुरंग के प्रवेश द्वार से निकालते हुए देखा गया है।सुरंग के ढहे हुए हिस्से के दूसरी ओर मौजूद कुछ श्रमिक 12 से 15 फीट ऊंचे ढीली मिट्टी के टीले को पार कर अपने कुछ अन्य साथियों तक पहुंचे। इसके बाद सभी को एक विशेष सुरंग वाहन के जरिए छोटे-छोटे समूहों में प्रवेश द्वार तक लाया गया। सुरंग से बाहर निकाले गए 27 श्रमिकों की पैरामेडिक्स द्वारा जांच की जा रही है।यह सुरंग भविष्य में अपशिष्ट जल ले जाने के लिए बनाई जा रही है। फायर डिपार्टमेंट के अनुसार, यह सुरंग 18 फीट चौड़ी है। घटनास्थल पर 100 से अधिक फायर डिपार्टमेंट के कर्मियों को तैनात किया गया था। जो संकीर्ण और सीमित स्थानों से बचाव में माहिर टीमें भी शामिल थीं।

नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद बचाव कार्य जारी ; सामान्य बारिश में जलस्तर तेजी से बढ़ने की होगी जांच

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद गुरुवार को भी राहत और बचाव कार्य जारी रहा। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अभी भी लोगों को निकाला जा रहा है। नेपाल के रासुवा जिले में बारिश के बाद बाढ़ आई, जिसमें नौ लोगों की मौत हो चुकी है और 19 लोग अभी भी लापता हैं। रासुवा जिले के मुख्य जिला अधिकारी अर्जुन पौडेल ने बताया कि सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है और 150 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। इनमें 127 विदेशी नागरिक शामिल हैं। इन लोगों को एयरलिफ्ट कर काठमांडू ले जाया गया। पौडेल ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाके में बिजली और टेलीफोन सेवाएं बाधित होने से बचाव और अन्य अभियान बाधित हुए हैं। उन्होंने कहा, हम फिलहाल चीन सीमा के जरिए सीमित संचार बनाए हुए हैं। टेलीफोन संपर्क बहाल करने और बिजली आपूर्ति फिर से शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। नेपाल पुलिस ने बताया कि मंगलवार सुबह आई बाढ़ के बाद लापता हुए 19 लोगों की तलाशी अभियान भी जारी है। लापता लोगों में छह चीनी नागरिक और दो पुलिसकर्मी शामिल हैं। काठमांडू से 120 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित रसुवा जिले में आई बाढ़ में नेपाल को चीन से जोड़ने वाला मैत्री पुल भी बह गया है। साथ ही रसुवागढ़ी जलविद्युत संयंत्र और नेपाल-चीन सीमा के पास स्थित ड्राई पोर्ट का कुछ हिस्सा भी बाढ़ में बह गया है। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बाढ़ में अब तक नौ लोगों की मौत हो चुकी है।

यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स का ऐतिहासिक फैसला

रूस को 2014 में मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट एमएच17 को मार गिराने का दोषी ठहराया

स्ट्रासबर्ग, एजेंसी। यूरोप की सर्वोच्च मानवाधिकार अदालत यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने एक ऐतिहासिक फैसले में रूस को 2014 में मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट एमएच17 को मार गिराने का दोषी ठहराया है। इस हादसे में विमान में सवार सभी 283 यात्रियों और 15 चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई थी। यह पहली बार है जब किसी अंतरराष्ट्रीय अदालत ने रूस को इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार ठहराया है।

17 जुलाई 2014 को एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रही मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट एमएच17 एक बोइंग 777 विमान था। यह फ्लाइट पूर्वी यूक्रेन के ऊपर से गुजर रही थी। उस समय यह क्षेत्र रूस समर्थित अलगाववादी विद्रोहियों के नियंत्रण में था। कोर्ट ने अपने 501 पेज के फैसले में कहा कि विमान को रूस में बनी सतह-से-हवा में मार करने वाली बक मिसाइल से जानबूझकर मार गिराया गया। रूस ने संभवतः इसे गलती से सैन्य विमान समझ लिया था। इस हमले में 17 देशों के 298 लोग मारे गए, जिनमें 198 डच नागरिक, 43 मलेशियाई, 38 ऑस्ट्रेलियाई और 10 ब्रिटिश नागरिक शामिल थे।

स्ट्रासबर्ग में भरे हुए कोर्टरूम में अदालत के प्रमुख मटियास गुओमार ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि रूस ने न केवल इस हमले के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करने से इनकार किया, बल्कि इसकी ठोस जांच करने में भी विफल रहा, जिससे पीड़ितों के परिजनों का दुख काफी बढ़ गया। अदालत ने रूस के इस रवैये को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना। इसके अलावा, रूस पर 2014 से यूक्रेन में व्यापक मानवाधिकार उल्लंघनों का भी आरोप लगाया गया, जिसमें हत्या, यातना, बलात्कार, नागरिक बुनियादी ढांचे का विनाश और यूक्रेनी बच्चों का अपहरण शामिल है।

यूक्रेन ने इस फैसले को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व करार देते हुए इसे एक निर्विवाद जीत बताया। यूक्रेन के न्याय मंत्रालय ने टेलीग्राम पर एक बयान में कहा कि यह फैसला अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत रूस की जवाबदेही को मजबूत करता है। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री कैस्पर वेल्डकैंप ने कहा, यह फैसला पीड़ितों के परिवारों के लिए न्याय और मान्यता की भावना प्रदान करता है, हालांकि यह उनके दुख को कम नहीं कर सकता।

रूस का रुख

रूस ने इस फैसले को अमान्य करार देते हुए इसे मानने से इनकार कर दिया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेसकोव ने कहा, हम इस फैसले का पालन नहीं करेंगे, हम इसे शून्य मानते हैं। रूस ने हमेशा इस हादसे में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है और दावा किया है कि यह यूक्रेनी सेना या अन्य कारणों से हुआ। हालांकि, कोर्ट ने अपने फैसले में साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट किया कि मिसाइल रूसी सैन्य बलों या रूस समर्थित अलगाववादियों द्वारा दागी गई थी। यह फैसला नीदरलैंड्स में हुई एक आपराधिक मुकदमे से अलग है, जिसमें 2022 में दो रूसियों और एक यूक्रेनी विद्रोही को अनुपस्थिति में हत्या के कई मामलों में दोषी ठहराया गया था। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वे अभी भी फरार हैं और रूस ने उन्हें प्रत्यर्पित करने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा, मई 2025 में संयुक्त राष्ट्र की विमानन एजेंसी, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन ने भी रूस को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया था।

सीरिया में कुर्द लड़ाकों और सरकार के बीच मतभेद

दमिश्क, एजेंसी। सीरिया की सरकार और कुर्द लड़ाकों के बीच सेनाओं के विलय को लेकर मतभेद बरकरार हैं। तुर्किये में अमेरिकी राजदूत टॉम बैरक को सीरिया में भी विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा है कि सीरिया की केंद्रीय सरकार और कुर्दों के बीच लंबी बातचीत के बावजूद गतिरोध खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि वार्ता के बाद भी सेनाओं के विलय की योजना को लेकर मतभेद बने हुए हैं।

उन्होंने कुर्द नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज के प्रमुख मजलूम आब्दी और सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा के साथ बैठक के बाद यह बात कही। बता दें कि इसी साल मार्च में अमेरिका समर्थित कुर्द लड़ाकों के नेतृत्व वाली सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस और देश की सरकार के बीच ऐतिहासिक समझौते हुए थे। समझौते के तहत, एसडीएफ बलों का नई राष्ट्रीय सेना में विलय कर दिया जाएगा और वर्ष के अंत तक इसके लागू हो जाने की उम्मीद है। समझौता लागू होने के बाद इराक और तुर्किये से लगी सभी सीमा चौकियां, पूर्वोत्तर में हवाई अड्डे और तेल क्षेत्र भी केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाएंगे। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट समूह के हजारों संदिग्ध सदस्यों को रखने वाले हिरासत केंद्र भी सरकार के नियंत्रण में आ जाएंगे। क्या एसडीएफ नई सेना में एक एकीकृत इकाई बनकर रहेगा या इसे भंग कर सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से नई सेना में शामिल किया जाएगा? इस सवाल पर सीरिया की राजधानी दमिश्क में बैठकों के बाद बैरक ने कहा, यह प्रश्न दोनों पक्षों के बीच एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है।

अमेरिका में भारतीय अरबपतियों का जलवा, पीछे छूटे चीन और इजरायल, जय चौधरी सबसे अमीर

वाशिंगटन, एजेंसी। भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए अमेरिका की प्रमुख अरबपतियों की लिस्ट में चीन और इजरायल को पीछे छोड़ दिया है। इस सूची में उद्यमी जय चौधरी को सबसे अमीर भारतीय-अमेरिकी के रूप में मान्यता दी गई है। फोर्ब्स की हाल ही में जारी की गई 'अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासी 2025' सूची में यह जानकारी दी गई। इसमें भारत को अमेरिका में अरबपति प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत देश बताया गया है। यह रिपोर्ट बुधवार को प्रकाशित हुई और इसमें भारत ने इजरायल और ताइवान को पीछे छोड़ दिया है।

फोर्ब्स के अनुसार, अमेरिका में रहने वाले विदेशी मूल के अरबपति नागरिकों की संख्या अब 125 हो गई है, जो 2022 में 92 थी। ये अरबपति अब अमेरिका की कुल अरबपति संपत्ति में 18प्रतिशत का योगदान दे रहे हैं, जिसकी कुल अनुमानित राशि 7.2 ट्रिलियन डॉलर है। प्रवासी अरबपतियों की कुल संपत्ति 1.3 ट्रिलियन डॉलर आंकी गई है, जो अब तक का रिकॉर्ड है।

भारत की बढ़ती मौजूदगी : 2022 में भारत से केवल 7 अरबपति प्रवासी अमेरिका में थे, जबकि इजरायल, कनाडा जैसे देश उससे आगे थे। लेकिन 2025 की सूची में भारत पहले स्थान पर आ गया है, जहां अब 12 भारतीय मूल के अरबपति प्रवासी शामिल हैं। इजरायल और ताइवान 11-11 अरबपतियों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। चीन भी 8 अरबपतियों के साथ सूची में है।

सबसे अमीर भारतीय-अमेरिकी: जय चौधरी : इस सूची में जीस्केलर के सीईओ और साइबरसिक्योरिटी के दिग्गज जय चौधरी को सबसे अमीर भारतीय-अमेरिकी अरबपति बताया गया है। उनकी कुल संपत्ति 17.9 बिलियन डॉलर (लगभग ?1.49 लाख करोड़) बताई गई है। अन्य प्रमुख भारतीय मूल के अरबपतियों में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और खोसला वेंचर्स के विनोद खोसला का नाम भी शामिल है।

सबसे अमीर प्रवासी अरबपति: एलन मस्क : फोर्ब्स के मुताबिक, एलन मस्क अमेरिका के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर प्रवासी अरबपति हैं। दक्षिण अफ्रीका में जन्मे मस्क कनाडा के रास्ते अमेरिका आए थे और उनकी कुल संपत्ति लगभग 400 बिलियन डॉलर है। दूसरे स्थान पर गूगल के सह-संस्थापक सर्गेई ब्रिन हैं, जिनकी संपत्ति 139.7 बिलियन डॉलर आंकी गई है। फोर्ब्स का कहना है कि अमेरिका के टॉप 10 अरबपतियों में से तीन प्रवासी मूल के हैं, जो यह दर्शाता है कि वैश्विक प्रतिभा किस तरह अमेरिका के आर्थिक परिदृश्य को आकार दे रही है।

चीन के छात्रों पर जासूसी का आरोप, विश्वविद्यालयों से चाइनीज छात्रवृत्ति को खत्म करने की मांग

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका की सत्ताधारी पार्टी रिपब्लिकन के कई सांसदों ने विश्वविद्यालयों से चीन समर्थित छात्रवृत्ति कार्यक्रम को खत्म करने की मांग की है। रिपब्लिकन सांसदों का दावा है कि चीनी छात्रवृत्ति कार्यक्रम की आड़ में चीन ने अमेरिकी तकनीक चुराने का कुटिल तंत्र बनाया हुआ है। रिपब्लिकन सांसदों ने सात विश्वविद्यालयों को पत्र लिखा है, जिनमें नोट्रे डेम विश्वविद्यालय, डार्टमाउथ भी शामिल हैं। चीन द्वारा समर्थित छात्रवृत्ति कार्यक्रम के जरिए हर साल सैंकड़ों चीनी छात्र अमेरिकी विश्वविद्यालयों से स्नातक होते हैं।

चीनी छात्रों पर प्रौद्योगिकी चुराने का आरोप

चीनी छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत चीनी छात्रों को अमेरिकी विश्वविद्यालयों से स्नातक होने के बाद चीन वापस जाना होता है और वहां दो साल काम करना होता है। कार्यक्रम के तहत चीन की सरकार अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए 50 फीसदी खर्च वहन करती हैं और साथ ही डॉक्ट्रेट की पढ़ाई करने के लिए स्टाइपेड भी देती है। मंगलवार को रिपब्लिकन सांसदों द्वारा भेजे गए पत्र में चीन की इस योजना को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया। अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन में रिपब्लिकन सांसद जॉन मूलेनार की अध्यक्षता वाली समिति ने पत्र में लिखा कि सीएससी कार्यक्रम, अमेरिकी और चीनी संस्थानों के बीच एक संयुक्त छात्रवृत्ति कार्यक्रम होने का दावा करता है। हालांकि, वास्तव में यह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बनाया गया एक प्रौद्योगिकी चुराने का प्रयास है, जो अमेरिकी संस्थानों का शोषण करता है और सीधे तौर पर चीन के सैन्य और वैज्ञानिक विकास को मदद करता है।

जिन सात विश्वविद्यालयों को रिपब्लिकन सांसदों ने पत्र लिखा है, उनमें नोट्रे डेम विश्वविद्यालय, डार्टमाउथ,

यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी, टेंपल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के डेविस, इर्विन और रिवरसाइड स्थित कैंपस शामिल हैं। कई विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि उन्होंने चीन की सरकार द्वारा समर्थित छात्रवृत्ति कार्यक्रम को बंद करने की योजना शुरू कर दी है। सांसदों ने विश्वविद्यालयों से चीनी घुसपैठ की जांच करने की भी मांग की है। साथ ही ये भी मांग की गई है कि चीन की छात्रवृत्ति योजना के तहत पढ़ाई करने वाले चीनी छात्र क्या अमेरिकी सरकार की फंडिंग से होने वाले रिसर्च कार्यक्रमों से तो नहीं जुड़े हैं, इसकी भी जांच की जाए।

अमेरिका की ट्रंप सरकार पहले ही अमेरिका पढ़ाई के लिए आने वाले चीनी छात्रों की सघन जांच कर रही है। ट्रंप ने चीन की नागरिक-सैन्य रणनीति से जुड़े छात्रों को भी वीजा नहीं देने का फैसला किया है। अहम और संवेदनशील विषयों की पढ़ाई करने वाले चीनी छात्रों का भी वीजा रद्द करने की बात ट्रंप प्रशासन ने कही है। हालांकि कई विश्वविद्यालयों ने चेताया है कि सभी चीनी छात्र जासूसी में शामिल नहीं हैं। गौरतलब है कि चीन से हर साल लाखों छात्र अमेरिका पढ़ाई के लिए जाते हैं। साल 2023-24 में भी 2,70,000 से ज्यादा चीनी छात्र पढ़ाई के लिए अमेरिका पहुंचे और अधिकतर की पढ़ाई का खर्च उनके परिजनों ने उठाया न कि चीन की सरकार ने।

भोजन और दवाइयों के लिए तड़प रहे गाजा के लोग, 10 इजरायली बंधकों को छोड़ने पर राजी हुआ हमास

गाजा , एजेंसी। हमास ने गाजा पट्टी में चल रहे संघर्ष के बीच 10 इजरायली बंधकों को रिहा करने पर सहमति जताई है। यह घोषणा तब हुई है जब इजरायली सेना के ताजा हमलों में गाजा में कम से कम 74 लोग मारे गए हैं। बंधकों की रिहाई को लेकर हमास ने कहा कि यह कदम युद्धविराम की दिशा में चल रही वार्ताओं का हिस्सा है। हालांकि उसने इजरायल पर अड़ियल रुख अपनाने का आरोप लगाया है।

युद्धविराम वार्ता में चुनौतियां : अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार, हमास ने बुधवार को बयान दिया कि कतर और अमेरिका की मध्यस्थता में चल रही वार्ताओं में कई बाधाएं हैं। इनमें गाजा में अत्यावश्यक सहायता की आपूर्ति, इजरायली सेना की वापसी, और स्थायी युद्धविराम के लिए वास्तविक गारंटी जैसे मुद्दे शामिल हैं। हमास के एक सीनियर लीडर ताहेर अल-नूनू ने अल जजीरा को बताया कि समूह ने 10

बंधकों की रिहाई के बदले भोजन, दवाइयां, और इजरायली हमलों को रोकने की मांग की है, जो उनके अनुसार मानवता की दिशा में एक कदम है। दूसरी ओर, इजरायली सैन्य प्रमुख इयाल जमीर ने एक टेलीविजन भाषण में कहा कि 10 जीवित बंधकों और नौ अन्य के शवों की रिहाई के लिए परिस्थितियां तैयार की गई हैं। हालांकि, युद्धविराम की संभावनाओं के बावजूद, इजरायली सेना ने गाजा में अपने हमले जारी रखे, जिसमें बुधवार को 74 लोग मारे गए। इनमें से आठ लोग गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन (जीएचएफ) के एक खाद्य वितरण केंद्र पर इंतजार कर रहे थे।

गाजा में मानवीय संकट : गाजा में इजरायली हमलों का सिलसिला जारी है, जिसने क्षेत्र को तबाह कर दिया है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजरायल पर आश्चर्यजनक हमले के बाद से गाजा में अब तक कम से कम 57,523 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा के बेत हानून में एक और बड़ा हमला शुरू किया, जो मंगलवार को हमास के एक आश्चर्यजनक हमले में पांच इजरायली सैनिकों की मौत के बाद हुआ। गाजा में मानवीय स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय एजेंसी ने चेतावनी दी है कि अस्पतालों में संसाधनों की कमी है, एम्बुलेंस रुक रही हैं, और जल आपूर्ति प्रणाली ढहने की कगार पर है। गाजा के इंडोनेशियाई अस्पताल के निदेशक मारवान अल-सुल्तान ने युद्ध के दौरान स्वास्थ्य प्रणाली के पतन के भयावह विवरण साझा किए हैं।

अंतरराष्ट्रीय प्रयास और विवाद : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर उम्मीद जताई कि जल्द ही युद्धविराम हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि इजरायल ने 60 दिनों के युद्धविराम की शर्तों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन हमास ने इस तरह के किसी समझौते को अस्वीकार करने की बात से इनकार किया।

ट्रंप के मध्य पूर्व दूत ने कहा कि इजरायल और हमास के बीच मतभेद कम हो रहे हैं, लेकिन कोई ठोस समयसीमा अभी तक तय नहीं हुई है।इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के पूर्ण निरस्त्रीकरण और गाजा से उसके शासन को हटाने की मांग की है। दूसरी ओर, हमास ने स्पष्ट किया है कि वह केवल तभी बंधकों को रिहा करेगा जब इजरायल स्थायी युद्धविराम और गाजा से अपनी सेना की पूर्ण वापसी पर सहमत होगा।गाजा में सहायता संकटगाजा में सहायता वितरण को लेकर भी विवाद बढ़ रहा है। गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन (जीएचएफ) के संचालन शुरू होने के बाद से, सहायता प्राप्त करने की कोशिश में 650 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं और लगभग 4,000 घायल हुए हैं।

बाइडन के पूर्व डॉक्टर का जवाब देने से इनकार, डॉ. केविन ने 5वें संविधान संशोधन का इस्तेमाल किया

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल के दौरान उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत को लेकर जांच कर रही है। इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब व्हाइट हाउस के पूर्व डॉक्टर डॉ. केविन ओ कॉनर ने बुधवार को बाइडन की सेहत से संबधित जांच के मामले में गवाही देने से इनकार कर दिया। उन्होंने अमेरिकी संविधान के पांचवें संशोधन के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सवालों के जवाब नहीं दिए।

बता दें कि रिपब्लिकन सांसद की तरफ से जो बाइडन की मानसिक और शारीरिक सेहत की जांच कर रहे हैं। साथ ही ये दावा भी कर रहे हैं कि बाइडन के कार्यकाल के दौरान कुछ नीतियां व्हाइट हाउस के ऑटोपेन (दस्तखत की मशीन) के जरिए पास हुईं, जो तब वैध नहीं मानी जाएंगी, अगर यह साबित हो गया कि बाइडन उस समय मानसिक रूप से अक्षम थे। हालांकि बाइडन ने इन आरोपों को बेतुका और झूठा बताया है।

डॉ. कॉनर ने क्यों नहीं दिया गवाही? : मामले में अब एक सवाल लगातार खड़े हो रहे है कि डॉ. ओ'कॉनर ने बाइडन की सेहत को लेकर चल रहे जांच में गवाही

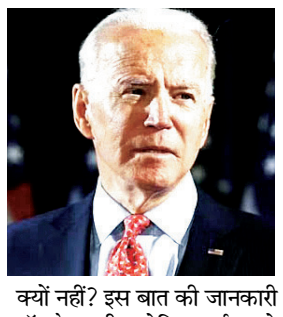

क्यों नहीं? इस बात की जानकारी डॉ. के वकील डेविड शर्टलर ने दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उन्हें एक डॉक्टर के रूप में मरीज की गोपनीयता बनाए रखनी थी और साथ ही न्याय विभाग की ओर से चल रही जांच में कानूनी जोखिम से भी बचना था।

जेम्स कोमर ने डॉक्टर के इनकार को बताया षडयंत्र : हाउस ओवरसाइट कमेटी के अध्यक्ष और रिपब्लिकन सांसद जेम्स कोमर ने डॉक्टर के इनकार को षड्यंत्र को छुपाने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी जनता पारदर्शिता चाहती है, लेकिन डॉ. ओ'कॉनर सच्चाई छुपा रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि किसी ने जांच के दौरान अमेरिकी संविधान के पांचवे संशोधन का सहारा लिया हो। इससे पहले भी कई गवाहों ने कांग्रेस की जांच में पांचवें संशोधन का सहारा लिया है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगियों ने 6 जनवरी, 2021 को कैपिटल हमले की जांच में जवाब देने से इनकार किया था।

बाइडन के कई पूर्व सहयोगी निशाने पर : बाइडन के सेहत को लेकर हो रहे जांच के दायरे में बाइडन के कई पूर्व वरिष्ठ सहयोगी भी हैं, जिनमें पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ रॉन क्लेन और जेफ जिएंट्स, वरिष्ठ सलाहकार माइक डोनिलन और अनिता डन, पूर्व डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ब्रूस रीड और एनी टोमासिनी, पूर्व राष्ट्रपति सलाहकार स्टीव रिचेटी के साथ-साथ पूर्व प्रथम महिला जिल बाइडन के चीफ ऑफ स्टाफ एंथनी बर्नाल का नाम शामिल है।

अफगानिस्तान में 6 साल की बच्ची की शादी: 45 साल के पुरुष से निकाह, तालिबान बोला- 9 साल की हो जाए तब ले जाना

काबुल, एजेंसी। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में 6 साल की एक बच्ची की शादी 45 साल के एक व्यक्ति से कर दी गई। अमेरिका स्थित अफगान आउटलेट एएमयू .टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक शादी की तस्वीरें सामने आने के बाद खुद तालिबान अधिकारी हैरान रह गए और बच्ची को उसके ससुराल ले जाने से रोक दिया। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि जब वह 9 साल की हो जाएगी, तब उसे पति के घर भेजा जा सकता है। दूल्हे ने बच्ची के परिवार को पैसे देकर यह रिश्ता तय करवाया। शादी हेलमंद के मर्जा जिले में हुई। इसके बाद पुलिस ने बच्ची के पिता और दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब तक किसी पर आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है।

तालिबान के 2021 में दोबारा सत्ता में आने के बाद, देश में न सिर्फ बाल विवाह की घटनाएं बढ़ी हैं, बल्कि उन्हें लेकर सामाजिक सहमति भी बनती जा रही है। लड़कियों की शिक्षा और काम पर पाबंदी के चलते कई परिवार बेटियों को बोझ मानकर जल्दी ब्याह दे रहे हैं। यूएन वूमेन की रिपोर्ट के अनुसार, तालिबान के महिला-विरोधी कानूनों के चलते देश में बाल विवाह में 25प्रतिशत और किशोरियों के गर्भधारण में 45प्रतिशत की वृद्धि हुई है।अफगान समाज में अक्सर लड़कियों को बचपन में ही नामकरण प्रथा के तहत किसी रिश्तेदार से मंगनी कर दी जाती है। इसे पारिवारिक संपत्ति की तरह देखा जाता है। कई इलाकों में वलवर यानी दहेज के रूप में पैसा लेकर लड़कियों की शादी तय होती है। यह रकम लड़की की खूबसूरती, सेहत और शिक्षा के स्तर के आधार पर तय होती है। द अफगान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में उरुजगान की एक महिला अमीरी ने बताया कि उन्होंने अपनी 14 वर्षीय बेटी की शादी 27 साल के पुरुष से 3 लाख अफगानी में कर दी। महिला ने बताया कि उनकी बेटी बहुत छोटी है, लेकिन घर में खाने को कुछ नहीं था, यही रास्ता बचा था। अफगान समाज में बाद नाम की प्रथा के तहत खून-खराबे वाले झगड़ों को सुलझाने के लिए लड़कियों को दुश्मन परिवारों को सौंप दिया जाता है।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

कमरे में जनरेटर चालू रहने के कारण धुआं कमरे में भर गया जिससे एक पुरुष और दो महिलाओं की मौत

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत के भाठा गांव में जनरेटर के धुएं से दम घुटने के कारण तीन लोगों की मौत होने की संदिग्ध घटना सामने आई है।

कमरे में जनरेटर चालू रहने के कारण धुआं कमरे में भर गया था, जिससे एक पुरुष और दो महिलाओं की मौत हो गई, ऐसा प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंच गया है।

तीनों मृतक वरिष्ठ नागरिक थे। रात को तीनों एक ही कमरे में सोए थे और सुबह जब परिवार के सदस्य कमरे में गए तो तीनों मृत अवस्था में मिले। प्रारंभिक दृष्टिकोण से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मौत जनरेटर के धुएं से हुई है। फिलहाल पुलिस ने तीनों की मौत का सही कारण जानने और जांच के लिए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की मदद ली है। तीनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली कारण स्पष्ट हो पाएगा।

मृतक बाबूलाल के बेटे सुनील पटेल (ढोडिया) ने बताया कि कमरे में मेरे पापा, मासी और रिश्तेदार दादी सो रहे थे। सुबह जब मैं उठा, तो दरवाजा खोला और इन लोगों को जगाने गया, लेकिन वे नहीं उठे। मैच खेलने के लिए सभी लोग यहां आए थे। तब मैंने सबको कहा कि भाई, 108 एम्बुलेंस और बाकी सबको खबर कर दो। ये लोग नहीं उठे। मैं उस वक्त कमरे में मौजूद नहीं था और इनकी मृत्यु हो चुकी थी। मृतकों में मेरे पापा, मासी और एक रिश्तेदार शामिल हैं।

एक महीने पहले मेरी मां का निधन हुआ था, और उसके बाद समाज की परंपरा के अनुसार मासी च्महिना फेरवानेज (शुद्धिकरण की रस्म) के लिए आती हैं। कल ही मासी और रिश्तेदार दादी यहां आए थे। मैं खुद पांच दिन पहले आया था। मेरे पापा यहां अकेले रहते थे और मैं इच्छापोर में रहता हूं। बीती रात मैं और मेरी पत्नी बगल के कमरे में ही सोए थे। कमरे में अंदर गए तो तेज दुर्गंध आ रही थी: PI

पाल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के. एल. गाधे ने बताया कि सुबह पीसीआर को एक कॉल मिला था कि भाठा गांव में तीन लोगों की मृत्यु हो गई है। यहां क्रिकेट ग्राउंड और खेत हैं। ये लोग खेत में चौकीदारी का काम करते थे। प्रारंभिक जांच के लिए जब हम मौके पर पहुंचे और जांच की, तो पता चला कि मृतकों में एक वृद्ध पुरुष और दो महिलाएं थीं। कमरे के अंदर जनरेटर चालू हालत में था और कमरा बंद था। जब हमने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया, तो अंदर से तेज दुर्गंध आ रही थी।

प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि जनरेटर के उपयोग के कारण कमरे में धुआं भर गया था, जिससे दम घुटने जैसी स्थिति बनी और इन लोगों की मौत हो गई। एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच की जाएगी। तब जाकर मौत का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा। जिस कमरे में लोग सो रहे थे, वहीं जनरेटर चलाया गया था। कमरे में वेंटिलेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे धुआं बाहर निकल सके। फिलहाल यही प्राथमिक जानकारी सामने आई है।

सूरत की सभी सुमन स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत नगर निगम द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के साथ-साथ माध्यमिक विद्यालयों के रूप में च्सुमन स्कूलोंज्ज की भी शुरुआत की गई है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी सुमन स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, स्कूलों में लगाए गए इन कैमरों की निगरानी सूरत नगर निगम के आईसीसीसी (इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर) से की जाएगी।

नगर निगम के स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी पढ़ते हैं। इन विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए स्कूल परिसर और आसपास की गतिविधियों पर नजर रखना अब आसान होगा और अनुशासनहीनता जैसी घटनाओं को रोका जा सकेगा। विजुअल मॉनिटरिंग से छात्रों और अभिभावकों का विश्वास भी बढ़ेगा और स्कूल प्रशासन अधिक जवाबदेह बनेगा।

इन सीसीटीवी कैमरों की मदद से स्कूल परिसर में अवांछित प्रवेश पर रोक लगाई जा सकेगी और अनुशासनहीनता तथा अनैतिक व्यवहार पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी। नगर निगम द्वारा लिए गए इस निर्णय के अनुसार कैमरों की निगरानी आईसीसीसी से की जाएगी, जिससे कुछ ही मिनटों में स्कूल में हो रही गतिविधियों की जानकारी मिल सकेगी।

सूरत के उधना में केमिकलयुक्त पानी सड़कों पर पालिका और GPCB जिम्मेदार हैं: भाजपा पार्षद

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत के उधना क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से नगरपालिका की ड्रेनेज में केमिकलयुक्त पानी छोड़े जाने की समस्या बनी हुई है। इस गंभीर मुद्दे पर पहले उधना के विधायक ने आवाज उठाई थी और गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (GPCB) की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे। अब भाजपा के ही पार्षद और ट्रांसपोर्ट कमिटी के अध्यक्ष सोमनाथ मराठा ने इस समस्या को लेकर पालिका और GPCB को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरी व्यवस्था में रिश्वतखोरी हो रही है और ऐसे कर्मचारियों व अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

उधना क्षेत्र में पालिका की ड्रेनेज और स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज में केमिकलयुक्त पानी छोड़े जाने की कई शिकायतें सामने आई हैं। पालिका द्वारा समय-समय पर कुछ डाइंग यूनिट्स को सील करने और ड्रेनेज कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई है। लेकिन कानून में ढील और कथित रिश्वतखोरी के चलते बार-बार सार्वजनिक रास्तों और ड्रेनेज में केमिकलयुक्त पानी बहने की शिकायतें हो रही हैं। कुछ दिन पहले विधायक मनु पटेल ने भी GPCB अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की थी कि वे फोन तक नहीं उठाते।

अब पार्षद सोमनाथ मराठा ने कहा कि वे पिछले तीन सालों से लगातार पार्टी की समन्वय बैठकों और सामान्य सभाओं में इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उधना क्षेत्र में गरीब, मध्यमवर्गीय और श्रमिक वर्ग के लोग रहते हैं और उनके आस-पास के इलाकों में ही डाइंग मिलें केमिकलयुक्त पानी छोड़ रही हैं। वर्तमान में मफतनगर क्षेत्र में यह समस्या गंभीर रूप से बनी हुई है।

सोमनाथ मराठा ने गंभीर आरोप लगाए कि उधना जोन में पूर्व कार्यपालक अभियंता सुजन प्रजापति की वजह से यह सब हुआ। उन्होंने इस क्षेत्र में अवैध कामों को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि पहले 42 डाइंग यूनिट्स को सील किया गया था, लेकिन वह कार्रवाई केवल दिखावा थी। कहीं न कहीं ड्रेनेज विभाग और इस कार्य से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी रिश्वतखोरी में लिप्त हैं।

उन्होंने मांग की है कि ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर कानूनी आपराधिक मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाए।

भाजपा के ही पार्षद द्वारा पालिका और GPCB अधिकारियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाने से राजनीतिक हलकों में गर्मी बढ़ गई है। आने वाले दिनों में यह विवाद और भी गहरा सकता है।

अग्रवाल विकास ट्रस्ट युवा शाखा की कार्यकारिणी का गठन

अंकित झुनझुनवाला अध्यक्ष, भारत सर्राफ सचिव बने

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत,अग्रवाल विकास ट्रस्ट युवा शाखा की वार्षिक साधारण सभा का आयोजन गुरुवार को रात आठ बजे से सिटी लाइट स्थित महाराजा अग्रसेन पैलेस के वृंदावन हॉल में किया गया। सभा में गत वर्ष में किए गए कार्यों एवं आयोजनों का विवरण दिया गया। सभा में नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। नई कार्यकारिणी में अंकित झुनझुनवाला को अध्यक्ष, मोहित भिवानीवाला को उपाध्यक्ष, भरत सर्राफ को सचिव, संचित गोयल को कोषाध्यक्ष, समवेद पंसारी को सहसचिव, सौरभ जालान को सहकोषाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा गर्ल पॉवर टीम में कीर्ति गर्ग, दिशिता गोयल, वर्षिता अग्रवाल एवं यशवी अग्रवाल को लिया गया।

इस मौके पर अग्रवाल विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रमोद पोद्दार, सचिव अनिल शोरेवाला, सहसचिव दिनेश अग्रवाल सहित युवा शाखा के अनेकों सदस्य उपस्थित रहें।

ड्रेनेज में केमिकल युक्त पानी छोड़ने वाली उधना में 8 अवैध यूनिट्स के ड्रेनेज कनेक्शन काटे गए

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत शहर में पिछले कुछ समय से नगरपालिका की ड्रेनेज में केमिकल युक्त पानी छोड़े जाने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। हाल ही में मेयर और विधायक द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षण और शिकायत के बाद अब तक 18 डाइंग यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसी क्रम में आज सूरत नगर निगम ने उधना इलाके में 8 अवैध डाइंग यूनिट्स के ड्रेनेज कनेक्शन काट दिए हैं।

हालांकि, इन कार्रवाइयों के बावजूद उधना क्षेत्र की सड़कों और पालिका की ड्रेनेज से अभी भी केमिकल और रंगीन पानी बहता देखा जा रहा है। शिकायतकर्ता और उधना के विधायक मनु पटेल का आरोप है कि जब वे GPCB (गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के अधिकारियों को फोन करते हैं तो वे कॉल रिसीव नहीं करते।

बीते रविवार को बारिश के बाद उधना क्षेत्र में कुछ औद्योगिक इकाइयों द्वारा केमिकल और रंगीन पानी बहाए जाने की शिकायत सामने आई थी। सूरत के मेयर दक्षेश मावाणी और विधायक मनु पटेल स्वयं मौके पर पहुंचे थे और अधिकारियों को मौके से ही फोन कर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद GPCB ने 4 डाइंग यूनिट्स को सील कर दिया था। इसके अलावा अब तक पालिका ने कुल 14 डाइंग यूनिट्स के ड्रेनेज कनेक्शन काटे हैं। कार्रवाई में पालिका ने उधना जोन में 21 डाइंग यूनिट्स की साइट विज़िट की, जिनमें से 8 अवैध यूनिट्स के ड्रेनेज कनेक्शन सील किए गए। शेष 13 यूनिट्स को बंद कर दिया गया या उनके द्वारा गलत उद्देश्य से किए जा रहे उपयोग को रोका गया।

उधना क्षेत्र में सार्वजनिक और पालिका की ड्रेनेज लाइनों में केमिकलयुक्त पानी छोड़े जाने से स्थानीय नागरिक परेशान हैं। विधायक मनु पटेल ने कहा कि सूरत पालिका ड्रेनेज कनेक्शन तो काट सकती है, लेकिन प्रदूषण फैलाने वाले इन औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करना GPCB की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि

प्रदूषण फैलाने वाली यूनिट्स को क्लोजर नोटिस मिलना चाहिए।

विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि जब वे GPCB के सूरत ज़ोन के अधिकारी को कॉल करते हैं, तो वह कॉल नहीं उठाते। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी यही बात कही थी। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर एक विधायक का कॉल GPCB अधिकारी नहीं उठाते, तो आम नागरिक GPCB में कैसे शिकायत कर सकता है? यह चर्चा का विषय बन गया है।

सूरत जिला कलेक्टर ने सभी पुलों की सघन जांच के आदेश दिए

खतरनाक संकेत मिलने पर पुल बंद करने के निर्देश, अधिकारियों को एक दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

वडोदरा जिले के मुझपुर-गंभीरा पुल जैसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सूरत जिला कलेक्टर डॉ. सौरभ पारधी ने तुरंत कार्रवाई की है। उन्होंने सूरत शहर और जिले के सभी पुलों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की और एक दिवसीय सघन निरीक्षण ड्राइव चलाने के आदेश दिए हैं।

जिला कलेक्टर कार्यालय के सभागार में आयोजित इस अहम बैठक में डॉ. पारधी ने नेशनल हाइवे अथॉरिटी, मेट्रो, मार्ग और मकान विभाग (राज्य और पंचायत), रेलवे, सूरत महानगरपालिका, सुदा (SUDA) और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी ओवरब्रिजों, नालों जैसे पुलों की तत्काल जांच और संरचनात्मक विश्लेषण किया जाए। इसके साथ ही,

प्रांत अधिकारियों, नायब जिला विकास अधिकारियों और मामलतदारों को भी अपने क्षेत्र के पुलों की जांच के आदेश दिए गए।

कलेक्टर ने विशेष रूप से जोर देकर कहा कि सूरत जिले में मौजूद सभी पुलों का तकनीकी विश्लेषण होना चाहिए।

यदि किसी पुल में जोखिम के संकेत दिखाई दें, तो तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। सबसे अहम निर्देश यह था कि ज़रूरत पड़ने पर सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे पुलों को ट्रैफिक के लिए तुरंत बंद कर दिया जाए।

इस बैठक में कलेक्टर ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी, राज्य और पंचायत मार्ग और मकान विभाग को निर्देश दिए कि वे अपने अधीनस्थ हर पुल की वर्तमान स्थिति की जांच कर एक दिन में स्टेटस रिपोर्ट सौंपें। उपस्थित सभी अधिकारियों ने अपने विभागों के अधीन पुलों की प्राथमिक जानकारी बैठक में प्रस्तुत की।

इस महत्वपूर्ण बैठक में SUDA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के.एस. वसावा, निवासी अतिरिक्त कलेक्टर विजय रबारी, मार्ग और भवन विभाग के कार्यपालक अभियंता (राज्य व पंचायत), रेलवे, मेट्रो, पुलिस, नगरपालिका के क्षेत्रीय अधिकारी, प्रांत अधिकारी, मामलतदार, चीफ ऑफिसर, हाईवे अधिकारी और DFCCIL के प्रोजेक्ट अधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

टूटे सड़कों से परेशान होकर सूरत म्युनिसिपल कमिश्नर ने अधिकारियों को दी चेतावनी, ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो तैयार रहना होगा 'शो कॉज़ नोटिस' के लिए

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

समीक्षा बैठक में नगर आयुक्त ने अधिकारियों पर जमकर गुस्सा निकाला। उन्होंने सख्त लहजे में कहा - अगर सड़कों की DLP (डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड) बाकी है तो क्या इसका मतलब ये है कि सड़कों पर गड्ढे बने रहें? केवल कागज पर काम दिखाकर बात नहीं बनेगी। अगर ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो तैयार रहो, मैं तुम सबको 'शो कॉज़ नोटिस' दूंगा।

कमिश्नर के इस आक्रामक रुख से बैठक में मौजूद अधिकारी चौंक गए।

शहर में सड़कों की हालत इतनी खराब है कि लोग परेशान होकर प्रशासन को कोसने लगे हैं। सड़कें इस कदर टूट चुकी हैं कि चलना मुश्किल हो गया है, लेकिन अधिकारी इनकी तुलना नेशनल हाईवे से करके जनता का मजाक उड़ा रहे हैं।

जब अधिकारियों ने जवाब दिया कि "टूटी हुई सड़कें DLP पीरियड में आती हैं, इसलिए ठेकेदारों से ही मरम्मत करवा लेंगेज्ज, तो आयुक्त भड़क उठे। उन्होंने साफ कहा - "DLP में है फिर भी गड्ढे क्यों हैं? जनता को इस तकलीफ का जिम्मेदार कौन है?"

अधिकारियों ने बैठक में दावा किया कि सूरत की कुल 4500 किलोमीटर सड़कों में से सिर्फ 0.55% यानी 24.90 किलोमीटर ही क्षतिग्रस्त हैं। इनमें से भी 21.88 किलोमीटर (87.82%) की मरम्मत हो चुकी है और सिर्फ 3.02 किलोमीटर सड़कें बची हैं।

इसी तरह कुल 2696 गड्ढों में से 2461 की मरम्मत हो चुकी है और सिर्फ 235 गड्ढे रह गए हैं। 299 मरम्मत योग्य सड़कों में से 224 को ठीक किया जा चुका है, जबकि 75 सड़कों पर काम बाकी है।

इन "जादुई आंकड़ों" से असंतुष्ट होकर कमिश्नर ने अधिकारियों को दो टूक कह दिया - "सिर्फ आंकड़े नहीं, मौके पर जाकर काम दिखाओ। ठेकेदारों को बचाने की कोशिश की तो खुद जिम्मेदार बनोगे। अगर अब भी सुधार नहीं हुआ तो कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।